घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 256- शुक्रवार 17- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

बारिश के बीच जय जगन्नाथ से गूंजा पुरी...तीनों रथों के दर्शन को उमड़ी भीड़

पुरी रथ यात्रा में भगदड़,एक श्रद्धालु की मौत,कई लोग घायल

भुवनेश्वर,16 जुलाई 2026। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। इस वर्ष यात्रा के दौरान मौसम का मिजाज थोड़ा अलग रहा और इंद्रदेव भी अपनी पूरी कृपा बरसाते नजर आए। भारी बारिश के बावजूद भगवान जगन्नाथ,उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के प्रति भक्तों की श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी नहीं दिखी। पुरी की सड़कों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु 'जय जगन्नाथ' के जयघोष के साथ एकत्र हुए। बारिश के कारण सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती और जल-जमाव से निपटने के लिए उठाए गए कदमों ने सुनिश्चित किया कि यह पवित्र अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। ओडिशा के पुरी में गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव के दौरान कथित भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस घटना में दम घुटने से एक श्रद्धालु की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि,प्रशासन की ओर से अभी तक श्रद्धालु की मौत या भगदड़ जैसी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान मरीचि कुंड चौक के पास अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। एक श्रद्धालु ने बताया कि बाहरी घेरे की रस्सी वाली बैरिकेडिंग गिर गई या फिर कुछ श्रद्धालु भीड़ के दबाव के कारण अपना संतुलन खो बैठे और सड़क पर गिर गए। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक,इस दौरान करीब 40 से 50 लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर गए, जिससे कई श्रद्धालुओं को चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कई लोगों को भीड़ से बाहर निकालकर एंबुलेंस और अस्पताल तक पहुंचाया गया। श्रद्धालु ने बताया कि उन्होंने स्वयं करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि एक बुजुर्ग श्रद्धालु की दम घुटने के कारण मौत हो गई है। वहीं,सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि गुरुवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और लगातार बारिश के बीच करीब 200 लोगों को घुटन, चोट और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पुरी के अस्पतालों और अस्थायी स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। पुरी में रथ यात्रा देखने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे। हर साल आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है। गुरुवार को पवित्र तटीय शहर में रथ यात्रा की शुरुआत निर्धारित समय से पहले ही भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए आयोजित 'पहंडी बीजे' अनुष्ठान के साथ हुई। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। पुलिस, अग्निशमन विभाग और आपदा राहत टीमों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद भारी भीड़ और मौसम की स्थिति के कारण कुछ स्थानों पर दबाव की स्थिति बन गई। पुरी में तैनात फायर और इमरजेंसी सर्विस के आईजी डॉ. उमाशंकर डैश ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पहली बार 25 स्पेशल रेस्क्यू यूनिट तैनात की गई थीं। प्रत्येक यूनिट में पांच प्रशिक्षित सदस्य और आधुनिक बचाव उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीमों ने अब तक करीब 100 लोगों को भीड़ में दबने और दम घुटने जैसी परेशानी से बचाया है। बचाए गए लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्थायी अस्पतालों और एंबुलेंस तक पहुंचाया गया। प्रशासन का कहना है कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि वे धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं।

अनोखी 'पहांडी' रस्म और भगवान का रथ पर पदार्पण

भारी वर्षा के कारण इस वर्ष 'पहांडी' रस्म में कुछ बदलाव किए गए। भगवान जगन्नाथ को बिना मुकुट पहनाए ही मंदिर से बाहर लाया गया और इस बार उन्हें झुलाते हुए नहीं, बल्कि अत्यंत सावधानी के साथ धीरे-धीरे रथ पर विराजमान किया गया। यात्रा से पूर्व पारंपरिक 'आज्ञामाला' रस्म पूरी की गई, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ का 'नंदीघोष',बलभद्र का 'तालध्वज' और देवी सुभद्रा का 'दर्पदलन' रथ श्री मंदिर के सिंहद्वार के सामने लाया गया। मंदिर के सेवायतों और भक्तों की उपस्थिति में यह धार्मिक परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई गई। इसके अलावा, चक्रराज श्री सुदर्शन को 'धाड़ी पहांडी' शोभायात्रा के जरिए उनके रथ तक पहुंचाया गया,जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्ति के सागर में डूब गया।

सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम और मॉक ड्रिल

लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए गए थे। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों और पुलिस की कड़ी निगरानी है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, ओड़िशा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, सेंट जॉन एम्बुलेंस, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने मिलकर एक संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भीड़ के नियंत्रण और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना था।

बंगाल की खाड़ी में भयावह हादसा....समुद्र में पलटीं 2 नाव,500 से ज्यादा लोगों की मौत

नई दिल्ली,16 जुलाई 2026। बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट के पास भयावह हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, यहां 500 से ज्यादा लोगों से भरी 2 नावें समुद्र में डूब गईं। इन दोनों नावों में अधिकांश रोहिंग्या समुदाय के लोग सवार थे,जिनका अब तक पता नहीं चला है। इस हादसे के बाद समुद्र में चीख-पुकार मच गई। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई। हालांकि अभी तक मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये नावें म्यांमार के गृहयुद्ध से जूझ रहे रखाइन प्रांत से जून महीने के आखिरी दिनों में रवाना हुई थीं।

नावों में सवार थे रोहिंग्या समुदाय के लोग : बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट के पास भयावह हादसा हो गया। खबरों के अनुसार, यहां 500 से ज्यादा लोगों से भरी 2 नावें समुद्र में डूब गईं। इन दोनों नावों में अधिकांश रोहिंग्या समुदाय के लोग सवार थे,जिनका अब तक पता नहीं चला है। इस हादसे के बाद समुद्र में चीख-पुकार मच गई। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई।

मृतकों की संख्या की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि : हालांकि अभी तक मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि हाल ही में पूरे इलाके में हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से ऐसी यात्राएं और भी ज्यादा जोखिम भरी हो गई होंगी।

हादसों को लेकर क्या बोला संयुक्त राष्ट्र : संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यह दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसों में शामिल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के तट के पास हुए इस बड़े समुद्री हादसे को लेकर गंभीर चिंता जताई है।

9वीं में तीसरी भाषा का बोझ न डालें : सुप्रीम कोर्ट

बोर्ड परीक्षा के एक साल पहले बच्चों में तनाव बढ़ेगा,सरकार से कहिए ऐसा न करें

नई दिल्ली,16 जुलाई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीबीएसई को 9वीं से थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं करनी चाहिए। 9वीं कक्षा की पढ़ाई पहले से मुश्किल है, ऐसे में तीसरी भाषा को शामिल करने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इससे स्टूडेंट्स का मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भारत सरकार से कहिए कि ऐसा न करें। जस्टिस बीवी नागरथना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि तीसरी भाषा को क्लास 5 या 6 में ही शुरू कर दिया जाना चाहिए,ताकि छात्र इसके साथ अधिक प्रभावी ढंग से तालमेल बिठा सकें। दरअसल,बेंच तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। तमिलनाडु सरकार जेएनवी में लागू थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी के पक्ष में नहीं है।

कोर्ट बोला...तीसरी भाषा की पढ़ाई 9वीं में बंद हो...

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि तीसरी भाषा को पढ़ाना 6वीं क्लास में शुरू करना चाहिए और 9 वीं में इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं का दबाव कक्षा 8 से ही शुरू हो जाता है। आगे उन्होंने अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं स्कूल में थी तब 8वीं के बच्चों को 10वीं की चीजें पढ़ाई जाती थीं। उस वक्त ऐसी हालत थी तो आप समझ सकते हैं आज बच्चों पर कितना बोझ होगा।

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार से बोली...यह रवैया न रखें

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के नवोदय विद्यालय शुरू करने के आदेश पर तमिलनाडु सरकार से कहा कि आपके यहां नवोदय विद्यालय होने चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी,आपको सिर्फ जमीन उपलब्ध करानी है। यह रवैया न रखिए। लेकिन तमिलनाडु सरकार के अनुरोध के बाद अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट का 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक से इनकार

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या अंग्रेजी को भारत की स्वदेशी (मूल) भाषा माना जा सकता है। साथ ही इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों को लेकर सरकार और सीबीएसई से 10 दिन में जवाब मांगा है। अब 14 दिन बाद 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल, थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी मौजूदा 2026-27 सेशन से लागू कर दी गई है। नई पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को 2 भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा पढ़नी होगी। ऐसे में उन्हें वे भाषाएं छोड़नी पड़ेंगी, जिन्हें वे क्लास 5 से लगातार पढ़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है था कि सीबीएसई ने तैयारी के बिना तीन-भाषा नीति लागू कर दी है। स्कूलों में पर्याप्त टीचर,किताबें और जरूरी एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है,जिससे स्टूडेंट-टीचर को परेशानी हो रही है।

वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला-हर जान कीमती,केंद्र-दिल्ली सरकार को आदेश-रोजाना मेडिकल जांच हो...

नई दिल्ली,16 जुलाई 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की जान कीमती है। उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराने और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। याचिका में जबरन खाना देने के निर्देश देने की मांग भी की गई थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकारी डॉक्टर वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर उचित इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक भी उनके आंदोलन में शामिल हैं। सीजेपी चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के बाद बनी थी।

समुद्री प्रशासन महानिदेशालय का बड़ा फैसला

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक

नई दिल्ली,16 जुलाई 2026। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए बड़ा निर्णय लिया है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) ने जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों तथा भर्ती एवं नियुक्ति सेवा लाइसेंसधारी कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। डीजीएमए ने अपने निर्देश में कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय भारतीय नाविकों के जीवन, सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखकर लिया गया है।

सोनिया गांधी के आवास पर हुई संसदीय दल की बैठक....मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी चंदे की चोरी,ई20 मामला भी उठाएगी कांग्रेस

नई दिल्ली,16 जुलाई 2026। सोनिया गांधी के आवास पर गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और जयराम रमेश समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा- पार्टी ने अपनी बैठक में कई प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा की और तय किया कि विपक्षी दलों के साथ मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार जिन प्रमुख विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही है, उनका पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा- कई मुद्दे ऐसे हैं, जिन्हें हम विशेष रूप से उठाएंगे। जैसे चंदे की चोरी और विश्वासघात। प्रभु श्रीराम मंदिर के संबंध में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हम अयोध्या में भाजपा और आरएसएस के रचे गए घोटाले का मुद्दा जरूर उठाएंगे। नीट और ई20 घोटाला जैसे कई मुद्दे भी हैं, जिसमें कई वरिष्ठ भाजपा नेता और उनके बेटे शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा- हमें पता चला है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री परिसीमन विधेयक को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार 17 अप्रैल को दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रही और इस विधेयक पर उसे बड़ा झटका लगा था। अब वह विधेयक को फिर से पेश करना चाहती है। कांग्रेस इस विधेयक का पहले भी विरोध करती रही है और आगे भी करती रहेगी। साथ ही विपक्षी दलों की एकजुटता बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। जयराम रमेश ने कहा कि न्यायाधीशों को हटाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी बैठक में चर्चा हुई। इस विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाई गई है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया है। कांग्रेस इस विधेयक का भी मजबूती से विरोध करेगी।

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू करें...तो पूरा समर्थन देंगे

जयराम रमेश ने कहा...हमने 16 और 17 अप्रैल को वर्तमान लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के संबंध में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम,2023 में महिलाओं के लिए इस एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान शामिल है। यदि आप 543 सदस्यीय लोकसभा का एक तिहाई मान लें,तो यह 181 आता है। इसलिए,महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू करें,और हम अपना पूरा समर्थन देंगे। हालांकि,परिसीमन विधेयक जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में पेश किया गया था,वास्तव में महिला आरक्षण की आड़ में लाया गया एक खतरनाक परिसीमन विधेयक था।

कांग्रेस एफसीआरए का भी विरोध करेगी- रमेश

यदि सरकार 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक' मानसून सत्र में लाती है तो कांग्रेस इसका पूरी तरह विरोध करेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक दोबारा लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी इस विधेयक का विरोध किया था,जिसके बाद सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। अगर इसे फिर पेश किया गया तो पार्टी दोबारा इसका विरोध करेगी।

100 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिलिंग मामले में स्क्रैप कारोबारी गिरफ्तार,अंतरराज्यीय सिंडिकेट की जांच तेज

जमशेदपुर,16 जुलाई 2026। करीब 100 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के मामले में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने जमशेदपुर के स्क्रैप कारोबारी अजय शर्मा को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी फर्जी कंपनियों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवैध लाभ दिलाने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़ा है। डीजीजीआई के संयुक्त निदेशक अभिनव कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान बारीडीह स्थित आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तलाशी में मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई डिजिटल दस्तावेज जब्त किए गए।

इसरो में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों से बढ़ी चिंता

इनमें गगनयान और दूसरे मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक भी...अब सरकार की सख्ती...

बेंगलुरु,16 जुलाई 2026। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन के गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अब पहले की तरह आसानी से मंजूरी नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष विभाग ने 14 जुलाई को नया निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्रुप ए वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन नियमित प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये निर्देश ऐसे समय आए हैं, जब पिछले 10 महीनों के दौरान 100 से ज्यादा कर्मचारी इसरो छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा इस्तीफे बेंगलुरु के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से हुए हैं। इस्तीफा देने वालों में वरिष्ठ वैज्ञानिक विक्टर जोसेफ टी भी शामिल हैं। वे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk III प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। बताया गया है कि उन्होंने फरवरी में इस्तीफा दिया। इससे पहले वे करीब 13 महीने तक LVM3 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यही लॉन्च व्हीकल गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा।

संपादकीय

गहरी पीड़ा देने वाला प्रकरण

भारतीय क्या स्वभाव से ही भ्रष्ट होते हैं? ऐसे भ्रष्ट कि भगवान राम तक को न बख्शें। दशकों से लोग जिस मंदिर के स्वप्न की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहे,उसी मंदिर से यह बात सामने आई कि जिन लोगों को इस पवित्र संस्थान की सेवा का दायित्व सौंपा गया था,वही शायद यहां चोरी या हेराफेरी करते रहे। यह किसी सरकारी विभाग,ऐरे-गैरे ठेकेदार या अनाम कंपनी से नहीं,बल्कि भगवान राम की संपदा में ही सेंधमारी का मामला है। याद रहे कि इस मंदिर निर्माण के संकल्प की पूर्ति में कई पीढ़ियां खप गईं। इस मुद्दे ने देश की राजनीति की दशा-दिशा को बदल कर रख दिया। समुदायों के बीच विभाजन की खाई खींच दी। पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और आधुनिक भारत के सर्वाधिक भावनात्मक मुद्दों में से एक बन गया।

जब राम जन्मभूमि मंदिर का स्वप्न वास्तव में साकार हुआ, तो दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने जश्न मनाया। अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए यह महज एक और मंदिर नहीं था,उनके लिए यही मंदिर था। ऐसे में यहां चोरी की घटना मन को गहरी टीस देने वाली है। यह कोई सामान्य भारतीय घपला-घोटाला नहीं कि किसी ने कोई गमला चुरा लिया या किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी काम के एवज में रिश्वत ली हो। एक ऐसे देश में जहां नैतिकता का पतन एक सामान्य परिपाटी बनता जा रहा हो,वहां राम मंदिर से चोरी का मामला कल्पनातीत ही प्रतीत होता है। गर्त में जा रही नैतिकता को अपनी नियति मान चुके समाज के लिए भी यह पाप की पराकाष्ठा है।

जिस प्रकरण ने समूचे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया, उसके उजागर होने पर भी हमने वही सब किया,जो ऐसी स्थितियों में करने के लिए विख्यात रहे हैं कहें कि कुख्यात रहे हैं। मसलन-कुछ खलनायकों को चिह्नित करो, कुछ को जेल भेज दो,कड़ी निंदा के साथ मामला रफा-दफा करने के साथ आगे बढ़ो। यह बहुत ही सहज प्रक्रिया है,लेकिन इसमें उस असहज करने वाली सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारत में भ्रष्टाचार महज कुछ लोगों की करतूतें से ही नहीं फलता-फूलता आया है। यह इस कारण भी अपनी पैठ जमाता गया,क्योंकि तमाम सामान्य भद्र जनों ने इसके साथ जीने और इसे अनदेखा करने के साथ ही इसके संग अनुकूलन की क्षमता विकसित कर ली और इस क्रम में जब कभी अवसर मिला, तो वे इससे लाभ उठाने से भी नहीं चूके।

हम इसी सोच के वशीभूत रहते हैं मानो भ्रष्टाचार केवल दूसरों की करतूत है- जैसे नेता,नौकरशाह और ठेकेदार ही इसके लिए जिम्मेदार हों। क्या वाकई ऐसा है? आखिर ये लोग हैं कौन? ये सभी हमारे इर्द-गिर्द के ही लोग हैं। कहीं न कहीं हमने भ्रष्टाचार को एक नैतिक नाकामी के रूप में लेना बंद कर उसे एक कौशल मानना शुरू कर दिया है। हमारे लिए कर चोरी करने वाला कारोबारी स्मार्ट, ऊपरी कमाई करने वाला सरकारी कर्मचारी पूरी तरह सेटल्ड और कानूनी विसंगतियों का फायदा उठाकर काम निकालने वाला संसाधन-संपन्न माना जाता है। निजी जीवन में ही इसके तमाम उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे अपनी लड़की के विवाह के लिए लिए सरकारी नौकरीपेशा लड़का खोज रहे अभिभावक लड़के की ऊपरी कमाई के बारे में पूछताछ को लेकर शायद ही झिझकते हों।

अक्सर हम धार्मिकता और नैतिकता को एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म के प्रति अतिशय आस्था रखने वाला व्यक्ति भी दैनंदिन जीवन में बेईमानी कर सकता है। भारतीय समाज में नैतिकता की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेने की एक विचित्र परिपाटी विकसित हो गई है। मतलब यह कि कारोबारी धोखाधड़ी हो या कमजोर लोगों का शोषण, ऐसा कोई भी पाप करो और किसी मंदिर को चंदा भेजकर स्वयं का आध्यात्मिक शुद्धीकरण समझ लो। मानो भगवान ने कोई पाप-पुण्य समायोजन सेवा चला रखी हो कि भगवान को दी गई रिश्वत से आपकी बेईमानी में ईमानदारी का भाव पैदा हो जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण ने ऐसी ही तमाम धारणाओं को ध्वस्त किया है। जब धर्म के आवरण वाले परिसर में भी लोभ पर नियंत्रण न रह जाए तो समझिए कि समस्या चरित्र में खोट की अधिक है और इसका समाधान भी अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई भरा है।

कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है। अन्य धर्मों, संस्थानों और देशों में भी ऐसे प्रकरण सामने आते रहते हैं। मान लिया कि यह भी सही है,लेकिन इससे क्या साबित होता है? कहीं और भ्रष्टाचार होने से यहां के भ्रष्टाचार का मामला कम शर्मनाक नहीं हो जाता। इसे हिंदू बनाम गैर-हिंदू का मुद्दा भी न बनाया जाए। इस मामले में जो आरोपित हैं,वे बाहर से आए हमलावर नहीं, बल्कि भीतर बैठे वे लोग हैं,जिन पर यहां सेवा एवं संचालन का दायित्व था।

इस प्रकरण से यही सीख मिलती है कि एक संस्थान केवल विश्वास के भरोसे ही न रहे। हमारी समस्या यह भी है कि हम कुछ लोगों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा कर उन्हें तमाम बुराइयों से परे मान लेते हैं। वास्तव में हमें प्रभावी तंत्र विकसित करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे होते हैं,लेकिन यह भी न भूला जाए कि मनुष्य अंततः मनुष्य ही होता है और उसके साथ गलतियों की गुंजाइश बनी रहती है। यह बात काफी हद तक सही है कि सभी भारतीय एक जैसे नहीं, लेकिन यह भी उतनी ही सही है कि अधिकांश तो ऐसे ही मिल जाएंगे। हम हिंदुओं के लिए यह बहुत पीड़ा देने वाला प्रकरण है।

अयोध्य राम मंदिर चंदा घोटाला

धर्म आस्था पर बड़ा प्रहार

केसी गुप्ता
द्वारका,नई दिल्ली

धर्म और आस्था प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। परंतु फिर भी इन दोनों के साथ समाज में सबसे अधिक खिलवाड़ होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म को राजनीति से जोड़ लोगो की भावनाओं को इस्तेमाल किया जाता है।इस विषय पर बात करना आसान नहीं । पिछ्ले कुछ दिनों से अयोध्या राम मंदिर की चोरी का विषय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस राम मंदिर के निर्माण और रामलला के आगमन का समस्त देशवासियों ने जश्न मनाया ।आज वही भव्य मंदिर विवादों के घेरे में है। तथाकथित तथ्यों पर आधारित मंदिर में चढ़ाए गए दान /चंदे में करोड़ों रुपए का घपला, चोरी की गई है। जिसे लेकर SIT की विशेष जांच समिति बनाई गई। समिति की जांच के दौरान ये खुलासा किया गया है कि दान पेटी की गिनती करने वाले कर्मचारियों ने ही सीसीटीवी कैमरा से छेड़ छाड़ कर गबन किया । उनके मोबाइल फोन द्वारा की गई कथित बातचीत से दो करोड़ की हेराफेरी की बात सामने आती है। कथित जांच के दौरान इन कर्मचारियों के और इन से संबंधित लोगों के बैंक खाते में पिछले 6 महीने में 10 लाख से अधिक की रकम के जमा होने का प्रमाण मिला

है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ़्तारी हो चुकी है । कई अन्य लोग जांच के दायरे में है । तथ्यों पर आधारित इसमें चंपत राय और गोपाल राव के नाम प्रमुख है। बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि मंदिर के कर्मचारी ही भगवान के घर में चोरी करने से नहीं डरते तो क्या ये आस्था ,धर्म का हनन नहीं? क्या इस तरह की चोरी मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह नहीं? तथ्यों पर आधारित इस संपूर्ण मामले को लेकर कुछ विवादित बयान जिसने श्रद्धा से दान नहीं दिया उस का पैसा चोरी हुआ है। मंदिर हमने बनाया है हम देख लेंगे इत्यादि देश की जनता में आक्रोश और अविश्वास पैदा कर रहा है। मामले को लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति तूल पकड़े हुए हैं। इस कथित मामले ने फिल्म उपकार के चर्चित गीत को यथार्थ कर दिया है कि ÷देते है भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। इस तरह के मामले देश के लोगों की आस्था और धर्म से जोड़ी भावनाओं पर एक बड़ा प्रहार है ।

रील्स नहीं,रियल स्किल्स बनाती हैं भविष्य

डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

डिजिटल युग ने अवसरों की दुनिया को पहले से कहीं अधिक विस्तृत बना दिया है। आज एक साधारण स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नई ऊँचाइयाँ दी हैं। अनेक युवाओं ने अपनी मेहनत,रचनात्मकता और निरंतर प्रयास के बल पर इस माध्यम से पहचान, सम्मान और आर्थिक सफलता भी प्राप्त की है। यह परिवर्तन निश्चित रूप से तकनीकी क्रांति का सकारात्मक पक्ष है। किंतु इसी चमकदार दुनिया का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे अक्सर लाइक्स, व्यूज़ और वायरल वीडियो की चकाचौंध ढँक देती है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में युवा पारंपरिक शिक्षा,व्यावसायिक कौशल और दीर्घकालिक करियर योजना की तुलना में सोशल मीडिया को ही सफलता का सबसे सरल और तेज़ रास्ता मानने लगे हैं। यह सोच जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उतनी ही जोखिमपूर्ण भी है।

आज सोशल मीडिया पर हमें वही लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने लाखों-करोड़ों रुपये कमाए,महंगी गाड़ियाँ खरीदीं,आलीशान घर बनाए और कुछ वर्षों में लोकप्रियता की ऊँचाइयाँ छू लीं। लेकिन कैमरे के पीछे एक विशाल दुनिया ऐसी भी है जहाँ लाखों लोग प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं,घंटों संपादन करते हैं, नए विचार खोजते हैं और फिर भी उन्हें न तो पर्याप्त दर्शक मिलते हैं और न ही आर्थिक स्थिरता। सफलता की कहानियाँ वायरल होती हैं,संघर्ष की कहानियाँ आँकड़ों में दब जाती हैं। यही चयनात्मक दृश्य युवाओं में भ्रम पैदा करता है कि यदि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया से जीवन बदल लिया है तो हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है।

वास्तविकता यह है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सफलता अत्यंत असमान रूप से वितरित होती है। कुछ प्रतिशत शीर्ष क्रिएटर्स अधिकांश दर्शकों, विज्ञापनों और आय पर अधिकार कर लेते हैं,जबकि शेष लाखों लोग सीमित अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। यह स्थिति केवल भारत में नहीं बल्कि विश्वभर में देखी जाती है। अधिकांश कंटेंट क्रिएटर्स अपनी सामग्री से स्थायी और सम्मानजनक आय

अर्जित नहीं कर पाते। इसलिए सोशल मीडिया को निश्चित करियर मान लेना आर्थिक दृष्टि से एक जोखिमपूर्ण निर्णय हो सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है या उस पर करियर बनाना गलत है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब युवा बिना किसी वैकल्पिक कौशल, शिक्षा या पेशेवर योग्यता के केवल वायरल होने की उम्मीद पर अपना भविष्य दाँव पर लगा देते हैं। इंटरनेट पर प्रसिद्धि प्राप्त करना और लंबे समय तक आर्थिक रूप से सफल बने रहना दो अलग-अलग बातें हैं। आज जो वीडियो करोड़ों लोग देख रहे हैं,संभव है कुछ महीनों बाद वही दर्शक किसी नए चेहरे की ओर आकर्षित हो जाएँ। डिजिटल दुनिया में लोकप्रियता का चक्र अत्यंत तेज़ गति से बदलता है।

सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती इसकी अनिश्चितता है। यहाँ आपका भविष्य केवल आपकी प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्लेटफ़ॉर्म के एल्गोरिदम,विज्ञापन नीतियों,कॉपी राइट नियमों,तकनीकी बदलावों और दर्शकों की बदलती पसंद पर भी निर्भर करता है। एक छोटे से एल्गोरिदमिक परिवर्तन से लाखों फ़ॉलोअर्स वाले अकाउंट की पहुँच अचानक घट सकती है। किसी नीति परिवर्तन से आय का प्रमुख स्रोत समाप्त हो सकता है। किसी तकनीकी त्रुटि या अकाउंट निलंबन से वर्षों की मेहनत प्रभावित हो सकती है। ऐसी अनिश्चितता किसी भी व्यक्ति के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा का आधार नहीं बन सकती।

इसके विपरीत वास्तविक कौशल की दुनिया कहीं अधिक स्थिर है। एक चिकित्सक की चिकित्सा-योग्यता,एक शिक्षक का ज्ञान,एक इंजीनियर की तकनीकी क्षमता,एक वकील का विधिक अनुभव,एक किसान की कृषि विशेषज्ञता,एक प्लंबर,इलेक्ट्रिशियन या

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

मशीन ऑपरेटर का व्यावसायिक कौशल किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर नहीं होता। समय के साथ तकनीक बदल सकती है,लेकिन वास्तविक कौशल की आवश्यकता समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि समाज की मूल संरचना शिक्षा,विज्ञान, चिकित्सा,कृषि,उद्योग और तकनीकी दक्षता पर आधारित रहती है,न कि केवल डिजिटल लोकप्रियता पर।

आज अनेक युवा पढ़ाई से अधिक समय रील बनाने,ट्रेंड खोजने और फ़ॉलोअर्स बढ़ाने में लगाने लगे हैं। कई बार विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी यह देखा जाता है कि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी से अधिक अपने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल की चिंता करते हैं। यह प्रवृत्ति चिंताजनक है,क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अर्जित ज्ञान और कौशल ही भविष्य की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं। यदि यही समय केवल तात्कालिक लोकप्रियता के पीछे व्यतीत हो जाए तो आगे चलकर प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

इस विषय का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। सोशल मीडिया लगातार तुलना की संस्कृति को बढ़ावा देता है। युवा दूसरों की सफलता देखते हैं,लेकिन उनके संघर्ष, असफलता और वर्षों की मेहनत नहीं देख पाते। परिणामस्वरूप उन्हें लगता है कि सफलता बहुत आसान है और यदि वे कुछ महीनों में लोकप्रिय नहीं हुए तो वे असफल हैं। यह सोच आत्मविश्वास को कमजोर करती है और मानसिक तनाव बढ़ाती है। वास्तविक जीवन में सफलता अक्सर वर्षों की तैयारी,अनुशासन,धैर्य और निरंतर अभ्यास का परिणाम होती है, जबकि सोशल मीडिया तत्काल परिणामों की अपेक्षा पैदा करता है।

यह भी सत्य है कि कंटेंट निर्माण स्वयं एक महत्वपूर्ण कौशल है। वीडियो संपादन,कहानी कहने की कला, कैमरा संचालन,ग्राफिक डिज़ाइन,डिजिटल मार्केटिंग और संचार क्षमता आज के समय में उपयोगी दक्षताएँ हैं। यदि कोई युवा इन कौशलों को व्यवस्थित रूप से सीखकर उन्हें किसी पेशे, व्यवसाय या विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है,तो सोशल मीडिया उसके लिए अत्यंत प्रभावी मंच बन सकता है। उदाहरण के लिए एक चिकित्सक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा कर सकता है,एक शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा दे सकता है,एक किसान आधुनिक कृषि तकनीक समझा सकता है, एक इंजीनियर तकनीकी समाधान प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामलों में सोशल मीडिया करियर नहीं बल्कि करियर का विस्तार बन जाता है।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब माध्यम ही उद्देश्य बन जाता है। मोबाइल कैमरा केवल एक उपकरण है, स्वयं में कोई पेशा नहीं। जिस प्रकार एक कलम लेखक नहीं होती,उसी प्रकार कैमरा भी सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता उस ज्ञान,अनुभव और मूल्य पर निर्भर करती है जिसे व्यक्ति अपने दर्शकों तक पहुँचाता है। यदि सामग्री के पीछे वास्तविक विशेषज्ञता नहीं होगी,तो लोकप्रियता टिकाऊ नहीं रह पाएगी।

आज भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। यह जनसांख्यिकीय शक्ति तभी लाभ में बदल सकती है जब युवाओं के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक दक्षता और नवाचार की क्षमता होगी। यदि बड़ी संख्या में युवा केवल डिजिटल प्रसिद्धि के सपने में वास्तविक कौशल अर्जित करने की प्रक्रिया से दूर हो जाएँ,तो इसका प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा।

सरकार,शैक्षणिक संस्थानों और परिवारों की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ करियर परामर्श,वित्तीय जागरूकता और कौशल विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। युवाओं को यह समझाना आवश्यक है कि सोशल मीडिया एक अवसर है, लेकिन यह सफलता का एकमात्र मार्ग नहीं है। परिवारों को भी बच्चों पर केवल पारंपरिक करियर थोपने के बजाय उनकी रुचियों को समझते हुए उन्हें संतुलित दिशा देनी चाहिए।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य का रोजगार बाजार तेजी से बदल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और नई तकनीकों के कारण अनेक पारंपरिक नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है। ऐसे समय में सबसे अधिक मूल्य उन लोगों का होगा जो निरंतर सीखने की क्षमता रखते हैं और जिनके पास मूलभूत कौशल के साथ नई तकनीक अपनाने की योग्यता होगी। सोशल मीडिया इस प्रक्रिया में सहयोगी हो सकता है,लेकिन उसका विकल्प नहीं।

युवाओं को यह समझना होगा कि प्रसिद्धि और सफलता समानार्थी नहीं हैं। लाखों लोगों द्वारा पहचाने जाना आवश्यक नहीं कि आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करे। इसके विपरीत अनेक ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लगभग अनजान हैं,लेकिन अपने पेशे में अत्यंत सफल, सम्मानित और आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। इसलिए करियर का चुनाव लोकप्रियता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता,रुचि,अवसर और दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सोशल मीडिया को न तो पूरी तरह नकारें और न ही उसे जीवन का अंतिम लक्ष्य बना दें। यह एक शक्तिशाली मंच है,जिसका उपयोग सीखने,सिखाने,व्यवसाय बढ़ाने, विचार साझा करने और समाज से जुड़ने के लिए किया जा सकता है। किंतु इसकी चमक से प्रभावित होकर यदि युवा शिक्षा, कौशल और पेशेवर विकास की उपेक्षा करने लगें, तो यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर हानिकारक होगा।

अंततः याद रखने योग्य बात यही है कि सभ्यताओं का निर्माण तात्कालिकलोकप्रियता से नहीं,बल्कि ज्ञान,श्रम, कौशल और नवाचार से होता है। सोशल मीडिया पर बनाई गई एक सफल रील कुछ दिनों तक चर्चा का विषय बन सकती है,लेकिन एक उत्कृष्ट चिकित्सक,वैज्ञानिक,शिक्षक, अभियंता,किसान,उद्यमी या कुशल कारीगर का योगदान पीढ़ियों तक समाज को दिशा देता है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे पहले अपने भीतर ऐसी योग्यता विकसित करें जिसकी स्वतंत्र पहचान और बाजार में वास्तविक कीमत हो। उसके बाद सोशल मीडिया को उस प्रतिभा को दुनिया तक पहुँचाने का माध्यम बनाएँ। यही संतुलित दृष्टिकोण उन्हें क्षणिक प्रसिद्धि नहीं,बल्कि स्थायी सफलता और सम्मान दिला सकता है। यदि चाहें,इसे और अधिक ओजपूर्ण, अख़बार की संपादकीय शैली या युवा प्रेरक भाषण के रूप में भी रूपांतरित किया जा सकता है।

मंदिरों में भ्रष्टाचार : वहां सुशासन की नई क्रांति का सूत्रपात हो...

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

भारत की पहचान केवल उसकी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक दर्शन से नहीं है,बल्कि उन मंदिरों से भी है जो करोड़ों लोगों की आस्था,विश्वास और जीवन का आधार हैं। अयोध्या का श्रीराम मंदिर,बद्रीनाथ धाम, माता वैष्णोदेवी,तिरुपति,काशी विश्वनाथ,सोमनाथ, सालासर बालाजी,खाटू श्यामजी जैसे मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं,बल्कि भारतीय आत्मा के जीवंत प्रतीक हैं। इन मंदिरों में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि यहां उन्हें केवल भगवान के दर्शन ही नहीं,बल्कि आत्मिक शांति और नैतिक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। लेकिन जब इन्हीं मंदिरों से चढ़ावे की चोरी, वित्तीय अनियमितताओं, वीआईपी संस्कृति,पुजारियों अथवा कर्मचारियों के अनुचित आचरण और श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आती हैं,तब केवल कोई संस्था बदनाम नहीं होती,बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था घायल होती है। हाल के वर्षों में श्रीराम मंदिर,बद्रीनाथ और अब माता वैष्णोदेवी मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिरों की व्यवस्था को केवल धार्मिक भावना के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जिस धन को श्रद्धालु भगवान का अर्पण मानकर समर्पित करते हैं, वह किसी व्यक्ति या समूह की निजी संपत्ति नहीं है। उस धन का प्रत्येक रुपया सार्वजनिक विश्वास की धरोहर है। यदि उसी में अपारदर्शिता या चोरी का संदेह पैदा हो जाए तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं,बल्कि धार्मिक विश्वास के साथ विश्वासघात है।

मंदिरों में बढ़ती अव्यवस्था का दूसरा गंभीर पक्ष है-वीआईपी दर्शन संस्कृति। आज देश का सामान्य श्रद्धालु कई-कई घंटे कतार में खड़ा रहता है। वृद्ध, महिलाएं, दिव्यांग और छोटे बच्चों के साथ आए परिवार कठिन परिस्थितियों में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मंत्री, विधायक, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति पहुंचता है,सामान्य

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

दर्शन रोक दिए जाते हैं और वीआईपी दर्शन शुरू हो जाते हैं। आम श्रद्धालु की लाइन रोक दी जाती है, उसके दर्शन का समय बाधित होता है और उसे यह एहसास कराया जाता है कि भगवान के दरबार में भी सभी बराबर नहीं हैं। यह स्थिति भारतीय संस्कृति और धर्म की मूल भावना के विपरीत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर के समक्ष राजा और रंक में कोई भेद नहीं होता। यदि मंदिरों में भी सामाजिक और राजनीतिक विशेषाधिकार का प्रदर्शन होगा तो यह धर्म के मूल स्वरूप का अपमान है। मंदिरों को लोकतांत्रिक समानता और आध्यात्मिक समरसता का सर्वोच्च उदाहरण बनना चाहिए,न कि सामाजिक असमानता का मंच।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में 'समान मन्दिर दर्शन नीति' लागू की जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा या अत्यंत विशिष्ट संवैधानिक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को सामान्य श्रद्धालुओं की कतार से अलग विशेष दर्शन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यदि किसी कारणवश सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो,तब भी आम श्रद्धालुओं के दर्शन बाधित नहीं होने चाहिए। भगवान के दरबार में सबसे बड़ा वीआईपी केवल श्रद्धा होनी चाहिए,पद और सत्ता नहीं। इसी प्रकार मंदिरों की चढ़ावा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आज डिजिटल भारत का युग है,फिर भी अनेक मंदिरों में दान और चढ़ावे की पारदर्शी व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी है। प्रत्येक बड़े मंदिर में दान-पात्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी,सीसीटीवी कैमरे,बारकोड आधारित सीलिंग, नियमित स्वतंत्र ऑडिट तथा प्रत्येक माह आय-व्यय का सार्वजनिक विवरण वेबसाइट और सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्रद्धालु को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा दिया गया धन कहां और किस उद्देश्य में उपयोग किया जा रहा है।

इसके साथ ही मंदिर प्रशासन में केवल धार्मिक पहचान ही नहीं,बल्कि चरित्र,ईमानदारी और प्रशासनिक दक्षता को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को स्थान मिले जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निष्कलंक हो,जिनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शी रहा हो और जिन पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या आपराधिक आरोप न हों। समय-समय पर उनके कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जाए। मंदिर प्रबंधन किसी का विशेषाधिकार नहीं,बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। मंदिरों में सेवा करने वाले पुजारियों,कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी आचार-संहिता बनाई जानी चाहिए। श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार,अभद्र भाषा,दलालों से मिलीभगत, नशाखोरी या किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई हो। सालासर बालाजी में बाउंसरों द्वारा श्रद्धालु की पिटाई और खाटू श्यामजी में मुख्य पुजारी से जुड़े विवाद जैसे प्रसंग यह संकेत देते हैं कि केवल धार्मिक पहचान पर्याप्त नहीं,बल्कि नैतिक अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है।

मंदिरों में दलाल संस्कृति भी समाप्त की जानी चाहिए। दर्शन,प्रसाद,पूजा और विशेष अनुष्ठानों के नाम पर होने वाली अनधिकृत वसूली श्रद्धालुओं के विश्वास को कमजोर करती है। सभी सेवाओं की दरें सार्वजनिक हों,ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध हो और किसी भी अतिरिक्त वसूली पर कठोर दंड का प्रावधान हो। भारत आज विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद दुनिया भर से करोड़ों लोग भारतीय मंदिरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। धार्मिक पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण आधार बन रहा है। ऐसे समय यदि मंदिरों की व्यवस्थाओं पर भ्रष्टाचार,कुप्रबंधन और अव्यवस्था के आरोप लगते हैं तो केवल मंदिर ही नहीं,बल्कि पूरे भारत की छवि प्रभावित होती है। विश्व यह संदेश ग्रहण करता है कि जिस देश ने धर्म और नैतिकता का संदेश दिया, वह अपने ही धर्मस्थलों को पारदर्शी नहीं बना पाया,वहां भी व्यापक भ्रष्टाचार पसरा है।

भारत सरकार और राज्य सरकारों को अब इस विषय पर व्यापक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। 'राष्ट्रीय मंदिर सुशासन आयोग' जैसी स्वतंत्र संस्था का गठन किया जा सकता है,जो बड़े मंदिरों की वित्तीय पारदर्शिता,प्रशासनिक जवाबदेही,दर्शन व्यवस्था और श्रद्धालुओं के अधिकारों की निगरानी करे। प्रत्येक मंदिर के लिए सेवा-मानक निर्धारित हों तथा शिकायत निवारण की समयबद्ध व्यवस्था हो। धार्मिक संगठनों और संत समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि सत्य,ईमानदारी,सेवा और उत्तरदायित्व है। यदि मंदिरों के भीतर ही इन मूल्यों का ह्रास होगा तो समाज को नैतिक दिशा कौन देगा? मंदिर केवल पूजा के केंद्र नहीं,बल्कि चरित्र निर्माण के विद्यालय भी होने चाहिए।

आज आवश्यकता किसी छोटे-मोटे सुधार की नहीं,बल्कि मंदिर प्रशासन में एक नैतिक क्रांति की है। यह क्रांति पारदर्शिता,जवाबदेही,समानता और सेवा के चार स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए। मंदिरों को तकनीक से जोड़ना होगा,वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और ऑडिट-आधारित बनाना होगा,वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना होगा तथा हर श्रद्धालु को समान सम्मान देना होगा। याद रखना होगा कि मंदिरों की सबसे बड़ी संपत्ति उनका स्वर्ण,रजत या चढ़ावा नहीं,बल्कि करोड़ों लोगों का विश्वास है। यदि विश्वास टूट गया तो सबसे भव्य मंदिर भी अपनी आत्मा खो देगा। इसलिए समय की पुकार है कि मंदिरों को भ्रष्टाचार से मुक्त,दर्शन व्यवस्था को समान, प्रशासन को पारदर्शी और सेवा को मानवीय बनाया जाए। यही भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी,यही भारतीय संस्कृति का वास्तविक सम्मान होगा और यही वह परिवर्तन होगा जो भारत को केवल आध्यात्मिक महाशक्ति ही नहीं, बल्कि नैतिक महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा।

हरेला,प्रकृति और मानवता के अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़,हरदा मध्य प्रदेश

उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में हरेला मात्र एक लोक पर्व नहीं,बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मध्य विद्यमान अटूट और पवित्र प्रेम का जीवंत प्रतीक है। यह पर्व हमें यह बोध कराता है कि हमारा अस्तित्व इस धरा की हरियाली और पारिस्थितिक संतुलन पर ही पूर्णतः निर्भर है। सावन के महीने में मनाए जाने वाले इस महापर्व पर हम न केवल देवी-देवताओं को हरेला अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को यह संस्कार भी सौंपते हैं कि मिट्टी से जुड़ना ही जीवन की सार्थकता है।हरेला का मूल संदेश वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में निहित है। इसके अंकुर हमें निरंतर यह याद दिलाते हैं कि यदि हम धरती का पोषण करेंगे,तो बदले में यह धरा हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करेगी। आधुनिकता की दौड़ में कंक्रीट के जंगलों के बीच सिमटते जा रहे समाज के लिए आज इस पर्व की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। पर्यावरण का क्षरण न केवल आपदाओं को निमंत्रण देता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों को भी कमज़ोर करता है। यह पर्व हमें आत्ममंथन का अवसर देता है कि हम प्रकृति के संरक्षक हैं या केवल उपभोगकर्ता? यह हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रत्येक शुभ कार्य के अवसर पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे,ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वही निर्मल वायु, जल और हरियाली मिल सके, जो हमारे पूर्वजों को विरासत में प्राप्त हुई थी। वास्तव में,यह त्यौहार हमें सिखाता है कि विकास की गति चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न हो,वह प्रकृति के विनाश की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन ही मानव सभ्यता की सुरक्षा की एकमात्र गारंटी है। आज के इस दौर में,जब जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती बन चुका है, उत्तराखंड का यह लोक पर्व संपूर्ण विश्व के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि खुशहाली का वास्तविक मार्ग प्रकृति की सेवा, समर्पण और संरक्षण में ही निहित है। अतः हरेला के इस पावन अवसर पर हमें न केवल पारंपरिक रस्मों का निर्वहन करना चाहिए, बल्कि सच्चे अर्थों में प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए पृथ्वी को हरा-भरा रखने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। स्मरण रहे, हमारी हरियाली ही हमारी वास्तविक संपत्ति है और भावी पीढ़ियों के लिए यही सबसे अमूल्य उपहार होगा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

गैंग्स ऑफ वासेपुर-अंबिकापुर कनेक्शन में बड़ी कार्रवाई...

मोहम्मद जाहिद और जुनैद गिरफ्तार,कई और पुलिस के रडार पर

शब्बीर आलम को भगाने के मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी...आईजी ने खुद संभाली जांच की कमान...

गैंगस्टर फरारी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन,जाहिद-जुनैद गिरफ्तार,बैदुल खान की मुश्किलें बढ़ीं...

17 दिन बाद पुलिस का शिकंजा कसना शुरू,शब्बीर फरारी कांड में दो गिरफ्तार, कई और निशाने पर...

सीसीटीवी और कॉल डिटेल से खुल रहे राज,गैंगस्टर फरारी मामले में दो गिरफ्तार...

गैंगस्टर को भगाने वालों पर पुलिस का शिकंजा,खरसिया नाका से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार...

आईजी की सीधी निगरानी में कार्रवाई तेज,गैंगस्टर फरारी कांड में पहली गिरफ्तारी...

-संवाददाता-
अंबिकापुर,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े आजीवन कारावास प्राप्त फरार गैंगस्टर शब्बीर (साबिर) आलम को झारखंड पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर फरार कराने के मामले में आखिरकार सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है,देर रात पुलिस ने मोहम्मद जाहिद और उसके पुत्र जुनैद खान को गिरफ्तार कर लिया,दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग स्वयं सरगुजा आईजी दीपक झा कर रहे हैं, वहीं,पुलिस अधीक्षक भी देर रात तक मामले की निगरानी में मौजूद रहे,पुलिस सूत्रों के अनुसार,यह कार्रवाई कई दिनों से जुटाए जा रहे तकनीकी साक्ष्यों,सीसीटीवी फुटेज,कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर की गई है,जांच अब केवल फरार गैंगस्टर तक सीमित नहीं रह गई है,बल्कि उन सभी लोगों तक पहुंच रही है जिन्होंने कथित रूप से पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली या आरोपी को भागने में सहयोग किया।

आईजी दीपक झा खुद कर रहे मॉनिटरिंग

सूत्रों के अनुसार इस संवेदनशील मामले में सरगुजा आईजी दीपक झा ने स्वयं कमान संभाल ली है,पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी लगातार अपडेट लिया जा रहा है ताकि जांच में किसी प्रकार की चूक न हो,बताया जा रहा है कि हर महत्वपूर्ण इनपुट की जानकारी सीधे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है, पुलिस अधीक्षक भी देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठकर कार्रवाई की समीक्षा करते रहे।

सीसीटीवी और कॉल डिटेल से खुल रही परतें...

जांच एजेंसियों के हाथ अब कई महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, इसके अलावा घटनास्थल और आसपास सक्रिय मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है, सूत्रों का कहना है कि पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के समय कौन-कौन लोग वहां मौजूद थे,किसने किससे संपर्क किया और फरार होने के बाद आरोपी किस रास्ते से निकला,इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

बैदुल खान की मुश्किलें बढ़ना तय...

इस पूरे मामले में पहले से अपराध दर्ज होने के बाद फरार चल रहे राजहंस बस संचालक बैदुल खान की मुश्किलें अब और बढ़ती दिखाई दे रही हैं,पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और बैदुल खान के कथित संपर्कों,मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड तथा उसके सहयोगियों की गतिविधियों की भी गहन जांच की जा रही है, यदि जांच में नए साक्ष्य सामने आते हैं तो कई और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं तथा अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है।

बस संचालक से जुड़े लोगों पर भी नजर...

सूत्रों के अनुसार पुलिस केवल गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है। बस संचालन से जुड़े कुछ लोगों, उनके नियमित संपर्कों तथा आने-जाने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रखी जा रही है,बताया जा रहा है कि कई लोगों को पुलिस ने रडार पर लिया है और उनके संबंध में तकनीकी जानकारी जुटाई जा रही है।

पटना से पकड़कर लाई गई पुलिस...

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को पुलिस कोरिया पटना से पकड़कर अंबिकापुर लाई है,दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है,गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद जाहिद,पिता-हाजी मोहम्मद अयूब,उम्र लगभग 58 वर्ष,निवासी खरसिया नाका,न्यू हबीब नगर,अंबिकापुर,जुनैद खान,पिता-मोहम्मद जाहिद,उम्र लगभग 30 वर्ष,निवासी खरसिया नाका,न्यू हबीब नगर,अंबिकापुर,इन दोनों के विरुद्ध धारा 221, 132, 126(2),296(बी),351 एवं 263 के तहत कार्रवाई की गई है,पुलिस दोनों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शब्बीर आलम को फरार कराने की पूरी साजिश कैसे रची गई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।

सोशल मीडिया भी जांच के दायरे में....

पुलिस की निगाह सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी है,घटना के बाद वायरल हुए वीडियो, पोस्ट, लाइव प्रसारण तथा अन्य डिजिटल सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन स्पष्ट की जा सके।

29 जून की घटना से शुरू हुआ था पूरा मामला...

गौरतलब है कि 29 जून 2026 को झारखंड पुलिस आजीवन कारावास प्राप्त फरार गैंगस्टर शब्बीर (साबिर) आलम को गिरफ्तार करने अंबिकापुर पहुंची थी। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर लिया और हंगामे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया,इसके बाद सरगुजा पुलिस ने बैदुल खान एवं अन्य के विरुद्ध अपराध दर्ज किया था। अब लगातार हो रही गिरफ्तारियां यह संकेत दे रही हैं कि जांच निर्णायक चरण में पहुंच रही है।

कई और गिरफ्तारी की संभावना...

पुलिस सूत्रों का कहना है कि अभी जांच जारी है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया जा सकता,पूरे मामले पर अब सभी की नजर इस बात पर है कि फरार गैंगस्टर शब्बीर आलम,बैदुल खान तथा अन्य फरार आरोपियों तक पुलिस कब पहुंचती है और क्या यह जांच केवल कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित रहेगी या पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी।

चोरी के संदेह में छह लोगों से पूछताछ,7 तिरपाल,50 लीटर डीजल और बैटरी जब्त

लखनपुर पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर आरोपियों को तहसीलदार न्यायालय में किया पेश

-संवाददाता-
लखनपुर,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले की लखनपुर थाना पुलिस ने चोरी के संदेह में छह लोगों से पूछताछ कर उनके कब्जे से 7 नग तिरपाल,50 लीटर डीजल और एक बैटरी जब्त की है। सामान के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए इस्तगासा तैयार कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को थाना लखनपुर की टीम ग्राम पुहपुटरा-चिलबील-कटकोना क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पुहपुटरा के कुछ लोगों ने चोरी का तिरपाल, डीजल और बैटरी छिपाकर रखा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह संदिग्धों से पूछताछ की। पूछताछ में अरविंद पैकरा (23),फेकूराम (40),जितेंद्र कुमार (24), सरजू रजक (24),बुधन राजवाड़े (25) एवं मनोज राजवाड़े (24),सभी निवासी ग्राम पुहपुटरा, के कब्जे से 7 तिरपाल,50 लीटर डीजल और एक बैटरी बरामद की गई। पुलिस ने संबंधित सामग्री के स्वामित्व

संबंधी वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तहसीलदार लखनपुर के समक्ष पेश किया गया। इस कार्रवाई में प्रशिक्षु उप निरीक्षक हर्ष कुमार, सहायक उप निरीक्षक परशु पैकरा, प्रधान आरक्षक प्रवीण चंद तिवारी, अजय पाण्डेय तथा आरक्षक दशरथ राजवाड़े,सुरेश गुप्ता, कुश सोनी और रामकुमार यादव की सक्रिय भूमिका रही।

सरगुजा को रायपुर से जोड़ने की नई पहल : अंबिकापुर-रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की मांग तेज

सुबह 4 बजे अंबिकापुर से और शाम 4 बजे रायपुर से ट्रेन चलाने का प्रस्ताव,ZRUCC सदस्य मुकेश तिवारी ने महाप्रबंधक को भेजा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के लाखों यात्रियों को राजधानी रायपुर तक तेज, सुविधाजनक और प्रतिदिन सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मुकेश तिवारी ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महा प्रबंधक,बिलासपुर को पत्र भेजकर अंबिकापुर- रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू करने का आग्रह किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि अंबिकापुर, सरगुजा संभाग का मुख्यालय होने के साथ-साथ सरगुजा,बलरामपुर और जशपुर

जिलों के लाखों लोगों का प्रमुख रेल केंद्र है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी, मरीज, व्यापारी, अधिवक्ता,शासकीय कर्मचारी और अन्य यात्री रायपुर एवं बिलासपुर की यात्रा करते हैं, लेकिन सुविधाजनक समय पर सीधी इंटरसिटी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने से उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुकेश तिवारी ने प्रस्ताव दिया है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन सुबह 4 बजे अंबिकापुर से रवाना होकर लगभग 11 बजे रायपुर पहुंचे, जबकि शाम 4 बजे रायपुर से चलकर रात 11 बजे अंबिकापुर पहुंचे। इस समय-सारिणी से यात्रियों को एक ही दिन में आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, जिससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान में संचालित अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस में लगातार बढ़ती भीड़ के कारण आरक्षण मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में नई इंटरसिटी ट्रेन न केवल यात्रियों का दबाव कम करेगी,बल्कि उत्तर छत्तीसगढ़ और राजधानी के बीच बेहतर रेल संपर्क भी स्थापित करेगी। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और पिट लाइन का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है, जो आगामी महीनों में पूरा होने की संभावना है। इसके बाद नई ट्रेन का संचालन तकनीकी और परिचालन की दृष्टि से पूरी तरह संभव होगा। मुकेश तिवारी ने याद दिलाया कि इस प्रस्ताव पर 26 मई 2025 को आयोजित 20वीं ZRUCC बैठक में चर्चा हुई थी और 23 फरवरी 2026 की 21 वीं ZRUCC बैठक में भी इसे संज्ञान में लेकर आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।

अब उन्होंने जनभावनाओं, बढ़ती यात्री संख्या और विकसित हो रहे रेल अधोसंरचना को देखते हुए इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग की है। नई इंटरसिटी सेवा शुरू होने से उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों को राजधानी तक तेज और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही रेलवे की आय में वृद्धि, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा तथा क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ट्रक से तिरपाल चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार,चोरी का तिरपाल बरामद

अमेरा खदान क्षेत्र में ट्रकों से डीजल व सामान चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य निकला आरोपी,अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले की लखनपुर थाना पुलिस ने ट्रक से तिरपाल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया गया तिरपाल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी चोरी सहित अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं तथा वह अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रकों से डीजल एवं कीमती सामान चोरी की घटनाओं में सक्रिय रहा है। पुलिस के अनुसार झारखंड के गढ़वा जिले के बचनी निवासी फिरोज खान ने 6 जुलाई को थाना लखनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई की रात अमेरा खदान से कोयला लोड कर ट्रक क्रमांक CG-15-DH-6832 से लौटते समय पुहपुटरा गांव के पास कुछ युवक मोटरसाइकिल से ट्रक का पीछा कर रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर पीछे से आवाज आने पर ट्रक रोककर देखा तो ट्रक पर बंधा करीब 7 हजार रुपये कीमत का वाटरप्रूफ नीला तिरपाल गायब था। उन्होंने बाडूल और उसके साथियों पर तिरपाल चोरी कर मोटरसाइकिल से भागने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान 15 जुलाई को अमेरा-चिलबिल क्षेत्र के ग्रामीणों ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे बाडूल उर्फ सर्वजीत उर्फ विवेक राजवाड़े (22 वर्ष),निवासी पुहपुटरा चिलबिलपारा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक से तिरपाल चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी ने यह भी बताया कि वह अपने साथियों के साथ अमेरा खदान क्षेत्र से गुजरने वाले ट्रकों से डीजल और अन्य कीमती सामान चोरी कर कम कीमत में बेच देता था तथा रकम आपस में बांट लेते थे। आरोपी की निशानदेही पर नवापारा रोड के पास खेत की मेड़ के नीचे झाड़ियों में छिपाकर रखा गया चोरी का तिरपाल बरामद कर जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में शामिल अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सूदखोरी की प्रताड़ना ने ली कारोबारी की जान...सुसाइड नोट से खुला राज,पुलिस ने सूदखोर को दबोचा,ऊंचे ब्याज और जान से मारने की धमकी से टूट गया था संदीप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के चर्चित कारोबारी संदीप अग्रवाल की आत्महत्या मामले में पुलिस जांच ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। शुरुआती तौर पर आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रही इस घटना में अब सूदखोरी, मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकियों का गंभीर पहलू सामने आया है। करीब दो सप्ताह तक चली जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि अत्यधिक ब्याज पर दिए गए कर्ज की वसूली के लिए आरोपी लगातार मृतक पर दबाव बना रहा था। ब्याज और मूलधन की रकम नहीं मिलने पर आरोपी ने कई बार जान से मारने की धमकी दी,जिससे मृतक

मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच मर्ग क्रमांक 44/2026 के तहत शुरू की गई थी। जांच के दौरान घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया। इसके बाद मृतक के पिता, पत्नी और अन्य परिजनों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन की

तकनीकी जांच कर कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाला, वहीं बैंक खाते के लेन-देन का भी बारीकी से विश्लेषण किया। जांच में सामने आया कि मृतक संदीप अग्रवाल और आरोपी पंकज चौधरी के बीच लंबे समय से पैसों का लेन-देन चल रहा था। दोनों के बीच कई बार फोन पर बातचीत भी हुई थी। बैंक ट्रांजेक्शन और तकनीकी साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने मृतक को ऊंची ब्याज दर पर रकम उधार दी थी। समय पर पैसा वापस नहीं मिलने पर वह लगातार ब्याज और मूलधन की मांग करते हुए दबाव बना रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी द्वारा दी जा रही धमकियों और लगातार मानसिक प्रताड़ना ने मृतक को गहरे तनाव में पहुंचा दिया। जांच के दौरान पुलिस को मिले सुसाइड नोट में भी मृतक ने अपनी परेशानी का जिक्र किया है। उसने लिखा कि आरोपी की प्रताड़ना और लगातार बढ़ते दबाव के कारण वह बेहद परेशान हो चुका है। पुलिस के अनुसार मृतक ने आत्महत्या से पहले अपने पिता और पत्नी को भी आरोपी द्वारा दी जा रही धमकियों की जानकारी दी थी। परिजनों के बयान भी पुलिस जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने। इन सभी तथ्यों के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 487/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण), धारा 351(3) (आपराधिक धमकी) तथा कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत मामला कायम किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल को आरोपी के विरुद्ध तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी पंकज चौधरी (50), निवासी राजेंद्र वार्ड, दरीपारा, अंबिकापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी गोलमोल जवाब देता रहा और मेमोरेण्डम कथन देने से भी इंकार करता रहा। हालांकि उसने घटना में प्रयुक्त मोबाइल पुलिस को सौंप दिया, जिसे जब्त कर जांच में शामिल किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले की विवेचना अभी जारी है और पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।

सुसाइड नोट बना सबसे बड़ा सबूत : पुलिस के मुताबिक मृतक के पास से मिला सुसाइड नोट इस पूरे मामले का सबसे अहम साक्ष्य साबित हुआ। इसमें मृतक ने अपनी मानसिक पीड़ा, आर्थिक दबाव और आरोपी द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का उल्लेख किया है। इसी के आधार पर जांच की दिशा बदली और पुलिस तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में सफल रही।

ड्रोन संचालन, स्नेक बाइट बचाव एवं अग्नि सुरक्षा पर पुलिस कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

-संवाददाता-
बलरामपुर,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में गुरुवार को पुलिस लाइन मैदान में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार करना था। प्रशिक्षण में सिल्वर विंग्स डिफेन्स एजेंसी के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव राजवीर सिंह एवं उनकी टीम ने ड्रोन संचालन की जानकारी दी। प्रतिभागियों को कानून-व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाओं और सर्च ऑपरेशन में ड्रोन के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया तथा इसका व्यावहारिक प्रदर्शन भी कराया गया। इसके अलावा जिला अस्पताल के डॉ. शांति नंदन मिंज एवं डॉ. सौरभ ने सर्पदंश से बचाव, विषैले एवं गैर-विषैले सांपों की पहचान तथा प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण में आग लगने की स्थिति में बचाव, अग्निशमन यंत्रों के सही उपयोग और दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस बल की दक्षता और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाते हैं। कार्यक्रम में पुलिस विभाग, वन विभाग और नगर सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक प्रमोद किसपोट्टा, मो. याकूब मेमन, रेंजर निखिल सक्सेना, रक्षित निरीक्षक श्यामलेश कुमार देवांगन सहित विभिन्न थाना-चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।

CMYK

भक्ति और उल्लास के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा,जयघोष से गूंजा शहर

केदारपुर जगन्नाथ मंदिर से दुर्गाबाड़ी तक निकली भव्य शोभायात्रा...नौ दिन मौसी के घर में विराजेंगे महाप्रभु

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा गुरुवार को शहर में श्रद्धा,आस्था और उत्साह के साथ निकाली गई। केदारपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से उत्कल समाज के तत्वावधान में गाजे-बाजे और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भव्य रथयात्रा निकली। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया तथा विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। रथयात्रा को लेकर उत्कल समाज ने कई दिनों से व्यापक तैयारियां की थीं। गुरुवार सुबह से ही श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। समाज के लोगों और श्रद्धालुओं ने रथ पूजा, नेत्र उत्सव, नवग्रह पूजन,छेरापहरा तथा पहंडी विजय सहित विभिन्न पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। पूजा-अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ,बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुसज्जित रथ पर विराजित किया गया। इसके बाद जयघोष और भजन-कीर्तन के बीच रथयात्रा प्रारंभ हुई। रथयात्रा तिवारी बिल्डिंग मार्ग, जोड़ापीपल और चौपाटी के समीप स्थित जगन्नाथ मंदिर होते हुए आकाशवाणी चौक,गांधी चौक,घड़ी चौक, संगम चौक और ब्रह्म रोड से श्रीराम मंदिर पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। कुछ देर विश्राम के बाद यात्रा जयस्तंभ चौक,सदर रोड, महामाया चौक, संगम चौक और देवीगंज रोड होते हुए दुर्गाबाड़ी पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कई स्थानों पर स्वागत मंच बनाए गए थे,जहां रथ की आरती उतारी गई और प्रसाद का वितरण किया गया। धार्मिक वातावरण और भगवान के जयघोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा।

नौ दिन मौसी घर में रहेंगे महाप्रभु : धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए महाप्रभु नौ दिनों तक दुर्गाबाड़ी स्थित मौसी घर में विराजमान रहेंगे। इस अवधि में वहां प्रतिदिन विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होंगे,जबकि केदारपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर का पट बंद रहेगा।

बाहुड़ा यात्रा के साथ होगी मंदिर वापसी

नौ दिन बाद बाहुड़ा यात्रा निकाली जाएगी,जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पुनः रथ पर सवार होकर केदारपुर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर लौटेंगे। मंदिर पहुंचने पर परंपरानुसार विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ रथयात्रा महोत्सव का समापन होगा। उत्कल समाज ने श्रद्धालुओं से नौ दिनों तक आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की।

मेमू ट्रेन से पहुंचे पिता का नाबालिग बेटा स्टेशन से लापता,अपहरण की आशंका

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

मेमू ट्रेन से अंबिकापुर पहुंचे एक व्यक्ति का नाबालिग बेटा रेलवे स्टेशन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। पिता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने अपहरण की आशंका में मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार,कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र के डबरीपानी निवासी पुन्नी लाल (40), जो वर्तमान में गांधीनगर थाना क्षेत्र के अजीरमापानी टंकी के पास किराए के मकान में रहता है, 14 जुलाई की शाम अपने नाबालिग बेटे के साथ मेमू ट्रेन से अंबिकापुर पहुंचा था। रेलवे स्टेशन के बाहर उसकी मुलाकात ट्रेन में साथ यात्रा कर रहे एक व्यक्ति से हुई। उक्त व्यक्ति ने उसे खाने-पीने के लिए अपने साथ चलने को कहा। विश्वास में आकर पुन्नी लाल उसके साथ स्टेशन के दूसरे छोर पर चला गया। खाना खाने के बाद नशे की हालत में पुन्नी लाल अपने बेटे के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर सो गया। कुछ समय बाद जब उसकी नींद खुली तो उसका बेटा उसके पास नहीं था। उसने स्टेशन परिसर और आसपास काफी तलाश की, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। पुन्नी लाल ने आशंका जताई है कि

किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद उसने गांधीनगर थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पिता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत शून्य पर अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा बच्चे की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर खोजबीन की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और बच्चे का जल्द पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

मॉन्टफोर्ट स्कूल में गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ इन्वेस्टिचर सेरेमनी

सांसद चिंतामणि महाराज ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद को दिलाई शपथ,नेतृत्व और अनुशासन का दिया संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

मॉन्टफोर्ट स्कूल,अंबिकापुर में गुरुवार को सत्र 2026-27 के लिए छात्र परिषद के अलंकरण (इन्वेस्टिचर सेरेमनी) का गरिमापूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज थे,जबकि अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य ब्रदर एस. गेब्रियल ने की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद विद्यालय के बैंड दल और विद्यार्थियों ने आकर्षक मार्च-पास्ट प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्राचार्य ब्रदर एस. गेब्रियल ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया तथा विद्यालय की शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को बैज एवं ध्वज प्रदान कर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। विद्यार्थियों ने विद्यालय के आदर्शों, अनुशासन और नेतृत्व के मूल्यों का पालन करने का संकल्प लिया। सत्र 2026-27 के लिए शुभम पांडेय को हेड बॉय, श्रेया खलखो को हेड गर्ल, सप्तऋषि मुखर्जी को स्कूल कैप्टन तथा नम्रता तिर्की को असिस्टेंट स्कूल कैप्टन बनाया गया। इसके अलावा विभिन्न हाउस,अनुशासन एवं खेल गतिविधियों के लिए भी छात्र-छात्राओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अपने संबोधन में सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि अनुशासन व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों से नेतृत्व को सेवा और उत्तरदायित्व का माध्यम मानते हुए समय का सम्मान करने,कठिन परिश्रम करने तथा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने 'विद्या धनं सर्वधनप्रधानम्' का उल्लेख करते हुए नियमित अध्ययन,माता-पिता के सम्मान और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। प्राचार्य ब्रदर एस. गेब्रियल ने नवनिर्वाचित छात्र परिषद को बधाई देते हुए कहा कि परिषद विद्यालय और विद्यार्थियों के बीच सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षकगण एवं अभिभावक उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ।

अंतरराज्यीय गांजा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई,16 करोड़ के नेटवर्क का किया भंडाफोड़

बसंतपुर पुलिस और ओडिशा एसटीएफ की एंड-टू-एंड जांच में 4 और आरोपी गिरफ्तार

सवाल उठा...संभागीय आबकारी उड़नदस्ता के 'सुपरमैन' रंजीत गुप्ता का हाथ ऐसे बड़े तस्करों तक क्यों नहीं पहुंचता?

-संवाददाता-
बसंतपुर/बलरामपुर,16 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सक्रिय अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए बसंतपुर पुलिस और ओडिशा एसटीएफ ने एंड-टू-एंड जांच के आधार पर चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

करीब 16 करोड़ रुपये मूल्य के 3,139.570 किलोग्राम गांजा की तस्करी से जुड़े इस नेटवर्क में अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि केवल गांजा जब्त कर मामला बंद नहीं किया गया,बल्कि महीनों तक तकनीकी और अंतरराज्यीय जांच कर सप्लाई नेटवर्क तक पहुंच बनाई गई। इधर, सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शन, कैप्सूल और अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाने वाली संभागीय आबकारी उड़नदस्ता की कार्यप्रणाली को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। जनचर्चा में यह सवाल उठ रहा है कि जब पुलिस अंतरराज्यीय नेटवर्क तक पहुंच सकती है,तो क्या अन्य एजेंसियां भी इसी तरह संगठित सप्लाई चेन तक पहुंचने की दिशा में समान स्तर की जांच कर रही हैं?

दो बड़ी बरामदगी से खुला पूरा नेटवर्क : पुलिस के अनुसार पहला मामला 29 दिसंबर 2025 का है, जब बसंतपुर पुलिस ने नारियल की भूसी में छिपाकर राजस्थान ले जाए जा रहे 1,198.460 किलोग्राम गांजा से भरे ट्रक को पकड़ा था। उस समय तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त किया गया था। दूसरा मामला 11 जून 2026 का है, जब राजस्थान नंबर के ट्रक से 1,941.110 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में कुल 3,139.570 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 करोड़ रुपये आंकी गई।

जीपीएस,तकनीकी जांच और पूछताछ से पहुंचे असली नेटवर्क तक : पुलिस ने बताया कि दूसरे मामले में गिरफ्तार आरोपी लोकेश शर्मा से पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली। ट्रक में लगे जीपीएस,मोबाइल ऐप के जरिए हुए संपर्क और तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि ओडिशा के सोनपुर जिले के लोपा ढाबा के पास ट्रकों में स्थानीय लोगों की मदद से गांजा लोड कराया जाता था। इसी आधार पर बसंतपुर पुलिस और ओडिशा एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बौध जिले में दबिश देकर दुर्वाशा साहु, सुबुधी साहु,प्रकाश खटुआ और अरुण कुमार राणा को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

केवल कैरियर नहीं, पूरे नेटवर्क पर प्रहार : इस कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिस ने केवल ट्रक चालक या मौके पर पकड़े गए लोगों तक जांच सीमित नहीं रखी। विवेचना को आगे बढ़ाते हुए उस नेटवर्क तक पहुंच बनाई, जहां से गांजा ट्रकों में लोड कराया जा रहा था। यही कारण है कि इसे एंड-टू-एंड जांच की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

सरगुजा संभाग में नशीली दवाओं पर लगातार कार्रवाई,लेकिन बहस भी जारी : दूसरी ओर,सरगुजा संभाग में संभागीय आबकारी उड़नदस्ता के प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में नशीले इंजेक्शन,कैप्सूल और अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। वाहिद अंसारी,मोशीम अंसारी,साहिल तिर्की,नितीश गुप्ता,प्रदीप राजवाड़े,सजाद अली,महबूब खान, आशा पांडेय और राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन जैसे मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। हालांकि,इन मामलों में भी अधिकांश कार्रवाई पूछताछ के आधार पर अगले कथित सप्लायर तक पहुंचने तक सीमित रही।

इसी कारण अब यह सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या नशीली दवाओं के पूरे अंतरजिला या अंतरराज्यीय नेटवर्क तक पहुंचने के लिए पुलिस, औषधि प्रशासन और आबकारी विभाग के बीच और व्यापक समन्वय की आवश्यकता है।

बड़ी कार्रवाई ने तुलना की बहस भी छेड़ी: बसंतपुर पुलिस और ओडिशा एसटीएफ की कार्रवाई ने यह दिखाया कि लंबी विवेचना,तकनीकी साक्ष्य और अंतरराज्यीय समन्वय के जरिए संगठित तस्करी नेटवर्क तक पहुंचा जा सकता है। इसी के साथ यह बहस भी तेज हो गई है कि नशीली दवाओं के मामलों में भी यदि इसी प्रकार बहु-एजेंसी और तकनीकी जांच को लगातार आगे बढ़ाया जाए,तो सप्लाई चेन की ऊपरी कड़ियों तक पहुंचने की संभावना और मजबूत हो सकती है।

थाने के सामने महिला अधिकारी से चेन स्नेचिंग बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

शहर में चेन स्नेचिंग की घटनाएं एक बार फिर सिर उठाने लगी हैं। इस बार बदमाशों ने ऐसी जगह वारदात को अंजाम दिया,जहां आमतौर पर लोग खुद को सबसे सुरक्षित मानते हैं। कोतवाली थाना के ठीक सामने स्थित जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय के मुख्य गेट पर गुरुवार दोपहर करीब 3.30 बजे बाइक सवार दो बदमाशों ने शिक्षा विभाग की सहायक संचालक के गले से सोने की चेन झपट ली और कुछ ही सेकंड में फरार हो गए। दिनदहाड़े और थाने से चंद कदम की दूरी पर हुई इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ पूनम तिवारी रोज की तरह गुरुवार को भी कार्यालय आई थीं। दोपहर में भोजन करने के लिए वह स्कूटी से घर गईं और करीब 3.30 बजे वापस कार्यालय लौटीं। उन्होंने कार्यालय के बाहर स्कूटी खड़ी की और जैसे ही मुख्य गेट की ओर बढ़ीं,पीछे से हेलमेट पहने बाइक सवार दो युवक पहुंचे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पातीं, पीछे बैठे युवक ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार से थाना चौक होते हुए महामाया चौक की ओर फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग भी बदमाशों को पकड़ नहीं सके। पीड़िता ने तत्काल कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीसीटीवी फुटेज बना जांच का अहम आधार : वारदात डीईओ कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में दोनों आरोपी हेलमेट पहने बाइक से आते और वारदात के बाद भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है,ताकि बदमाशों के भागने का रूट पता लगाया जा सके।

थाने के सामने वारदात से बढ़ी चिंता :

घटना का सबसे गंभीर पहलू यह है कि चेन स्नेचिंग कोतवाली थाना के सामने हुई। इससे पहले भी शहर में चेन स्नेचिंग और झपटमारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में थाने के सामने महिला अधिकारी को निशाना बनाए जाने से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कार्यालयीन समय में भी बदमाशों के बेखौफ होकर वारदात करने से यह साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

CMYK

कागजों में बने तालाब,जमीन पर गड्ढे! सोनहत वन विभाग के 'जल संरक्षण' पर करोड़ों के खेल का आरोप

रातों-रात मशीनों से खोदे गड्ढे,तालाब के नाम पर सरकारी राशि खर्च! सोनहत वन विभाग पर गंभीर सवाल

राजन पाण्डेय

सोनहत/कोरिया,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के सोनहत वन परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा कराए गए कथित तालाब निर्माण कार्य अब गंभीर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं,जल संरक्षण,वन्यजीवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जाने का दावा किया गया है,लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि धरातल पर वास्तविकता बिल्कुल अलग है,उनका कहना है कि जहां कागजों में तालाब तैयार दिखाए गए हैं,वहां मौके पर केवल उथले गड्ढे नजर आ रहे हैं,यदि पूरे मामले का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन कराया जाए तो करोड़ों रुपये की योजनाओं में गंभीर अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि विभाग ने मजदूरों से कार्य कराने के बजाय रात के अंधेरे में जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर तेजी से मिट्टी खुदवाई,ताकि बरसात शुरू होने से पहले निर्माण कार्य पूर्ण दिखाकर भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर अच्छी बारिश हो जाती तो पानी भर जाने के कारण निर्माण की वास्तविक स्थिति कभी सामने ही नहीं आती,लेकिन इस बार अपेक्षित वर्षा नहीं होने से कथित तालाबों की वास्तविक तस्वीर उजागर हो गई।

तालाब कम,खानापूर्ति ज्यादा...

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी मापदंडों के अनुसार तालाब निर्माण में निश्चित गहराई, चौड़ाई,मजबूत पाल (मेड़),जल रोकने की व्यवस्था और तकनीकी मानकों का पालन अनिवार्य होता है,लेकिन जिन स्थानों पर तालाब बनाए जाने का दावा किया गया है,वहां न पर्याप्त गहराई दिखाई देती है, न मजबूत पाल और न ही ऐसा कोई ढांचा जिससे लंबे समय तक पानी का संरक्षण हो सके,ग्रामीणों का आरोप है कि कई स्थानों पर केवल मिट्टी हटाकर फोटो खिंचवा लिए गए और बाद में कागजों में इन्हें पूर्ण निर्माण दर्शा दिया गया,उनका कहना है कि यदि इन तथाकथित तालाबों का तकनीकी निरीक्षण कराया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप हुआ भी है या नहीं।

क्या मजदूरों का रोजगार छीनने के लिए चली मशीनें?

पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल रोजगार को लेकर उठ रहे हैं,आरोप है कि जिस कार्य को स्थानीय मजदूरों से कराया जा सकता था, उसे भारी मशीनों से कराया गया,ग्रामीणों का कहना है कि सोनहत क्षेत्र आदिवासी एवं ग्रामीण बाहुल्य इलाका है,जहां बड़ी संख्या में लोग मजदूरी पर निर्भर हैं,ऐसे समय में यदि विभाग श्रम आधारित कार्य कराता तो दर्जनों परिवारों को रोजगार मिलता,लेकिन इसके विपरीत जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर कुछ ही दिनों में कार्य पूरा दिखा दिया गया,स्थानीय लोगों का आरोप है कि मशीनों के उपयोग के पीछे केवल तेजी नहीं बल्कि भुगतान और कमीशन से जुड़ा खेल भी हो सकता है,हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही संभव होगी।

वन्यजीवों के लिए बने तालाब या पहली बारिश में बह जाने वाले गड्ढे?-वन विभाग का दावा रहता है कि ऐसे तालाब वन्यजीवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने तथा जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान स्थिति में बने ढांचे न तो वन्यजीवों की प्यास बुझा पाएंगे और न ही जल संरक्षण का उद्देश्य पूरा कर पाएंगे, उनका कहना है कि बिना मजबूत पाल और पर्याप्त गहराई वाले ये गड्ढे पहली तेज बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

नए रेंजर के कार्यकाल पर भी सवाल

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नए रेंजर की नियुक्ति के बाद लोगों को उम्मीद थी कि वन विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा,लेकिन अब उन्हीं के कार्यकाल में इस प्रकार के आरोप सामने आने से लोगों में निराशा है,ग्रामीणों का आरोप है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे किसी भी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि इन आरोपों पर विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब जांच ही बताएगी सच्चाई...

वन विभाग पर लगे ये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं,यदि इनमें तथ्य हैं तो यह केवल निर्माण गुणवत्ता का मामला नहीं बल्कि सरकारी धन के उपयोग,तकनीकी स्वीकृति,कार्य निष्पादन, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा विषय बन सकता है,अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कथित तालाबों का स्वतंत्र तकनीकी एवं भौतिक सत्यापन कराया जाएगा? क्या प्रत्येक निर्माण की स्वीकृत राशि और वास्तविक कार्य का मिलान होगा? क्या मशीनों के उपयोग और मजदूरों को काम न मिलने की जांच होगी? क्या 15 जून के बाद मिट्टी कार्य होने के आरोपों की जांच की जाएगी? यदि अनियमितता मिलती है तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे, फिलहाल ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाई जाए, ताकि यदि कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है तो दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके।

15 जून के बाद भी जारी रहा मिट्टी का कार्य?

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 जून के बाद सामान्यतः मिट्टी से जुड़े कार्य बंद कर दिए जाते हैं,क्योंकि मानसून शुरू हो जाता है,इसके बावजूद सोनहत क्षेत्र में कथित रूप से मशीनों से खुदाई का कार्य जारी रहा,यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल गुणवत्ता का नहीं बल्कि शासन के आदेशों की अवहेलना का भी गंभीर मामला माना जाएगा।

न सूचना पटल,न पारदर्शिता...

ग्रामीणों का कहना है कि जिन स्थानों पर निर्माण कराया गया वहां अधिकांश जगहों पर सूचना पटल तक नहीं लगाया गया,लोगों को यह तक जानकारी नहीं है कि कार्य किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुआ,कितनी राशि मंजूर हुई और किस एजेंसी द्वारा कराया गया,स्थानीय वन समिति के सदस्यों का भी दावा है कि उन्हें निर्माण कार्यों की जानकारी नहीं दी गई,इससे कार्यों की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

जन सहयोग समिति ने खोला मोर्चा...

जिला पंचायत कोरिया जन सहयोग समिति के उपाध्यक्ष राजू साहू ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है,उन्होंने कहा कि सभी कथित तालाबों का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन कराया जाए और प्रत्येक निर्माण स्थल की लंबाई,चौड़ाई,गहराई, पाल,स्वीकृत लागत तथा भुगतान का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए,उन्होंने कहा कि यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

पुष्पेंद्र राजवाड़े ने लगाए गंभीर आरोप...

जन सहयोग समिति से जुड़े पुष्पेंद्र राजवाड़े ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला जल संरक्षण से अधिक मशीन आधारित निर्माण और सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रतीत होता है, उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में गरीब आदिवासी मजदूरी के लिए भटक रहे हों, वहां मशीनों से रातों-रात कार्य कराना कई सवाल खड़े करता है, उन्होंने आरोप लगाया कि 15 जून के बाद भी मिट्टी कार्य जारी रखना नियमों की अनदेखी है, राजवाड़े ने कहा कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जन सहयोग समिति ग्रामीणों के साथ आंदोलन करेगी।

तालाब या खानापूर्ति? सोनहत वन विभाग के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप, भौतिक सत्यापन की मांग...

15 जून के बाद भी चलता रहा मिट्टी का काम! सोनहत वन विभाग पर नियमों की अनदेखी और करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप...

मजदूरों का हक छीना, मशीनों से कराया काम! सोनहत वन विभाग के तालाब निर्माण पर उठे बड़े सवाल...

'जल संरक्षण' के नाम पर खेल? कागजों में तालाब, मौके पर सिर्फ गड्ढे; सोनहत वन विभाग जांच के घेरे में...

सोनहत वन विभाग में तालाब निर्माण घोटाले की आशंका, ग्रामीण बोले—जांच हुई तो खुलेगी करोड़ों की पोल...

तालाब कम, भ्रष्टाचार ज्यादा! वन विभाग के निर्माण कार्यों पर उठे सवाल, उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज

सरकारी पैसे से 'कागजी तालाब'! सोनहत वन विभाग पर नियमों की धज्जियां उड़ाने और मशीनों से काम कराने का आरोप...

सोनहत में 'तालाब कांड' का आरोपः रात में चली जेसीबी,दिन में तैयार हुई फाइलें,अब भौतिक सत्यापन की मांग...

राम मंदिर चढ़ावा हमला...श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : टीएस सिंहदेव

अंबिकापुर में प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार से मांगा जवाब,जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की उठाई मांग

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे और श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने अपना हमला और तेज कर दिया है। गुरुवार को अंबिकापुर के राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह राजनीतिक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास का मामला है। ऐसे में यदि धन के उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार और ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि पूरे मामले में पारदर्शिता बरती जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए।

सिंहदेव ने कहा कि भगवान श्रीराम देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। मंदिर निर्माण के लिए देश-विदेश से श्रद्धालुओं ने स्वेच्छा से आर्थिक सहयोग दिया। लोगों ने यह विश्वास कर दान दिया

था कि राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होगा, लेकिन अब जिस तरह वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उससे श्रद्धालुओं के मन में भी संशय पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े घटनाक्रम, तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे तथा ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। ऐसे मामलों में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। यदि कोई अनियमितता नहीं हुई है तो फिर स्वतंत्र जांच से बचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे और चढ़ावे का उपयोग किस प्रकार किया गया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।

कांग्रेस ने रखीं पांच प्रमुख मांगें : प्रेसवार्ता के दौरान टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की ओर से पांच प्रमुख मांगें भी सामने रखीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दें, कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए, वर्तमान ट्रस्ट को भंग कर नई पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए तथा मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे, चढ़ावे और खर्च का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या राम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं कर रही है। पार्टी केवल यह चाहती है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए धन का पूरा हिसाब सार्वजनिक हो और यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो। उनका कहना था कि आस्था के नाम पर जुटाई गई राशि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार और ट्रस्ट दोनों की जिम्मेदारी है। प्रेसवार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक,शफी अहमद, हेमंत सिन्हा,सीमा सोनी, संजय विश्वकर्मा, द्वितेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाजयुमो में नई जिम्मेदारियां,शुभम जायसवाल बने सरगुजा संभाग प्रभारी, कोमल पटेल को सूरजपुर जिला प्रभारी की कमान

प्रदेश नेतृत्व ने की महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियां, कार्यकर्ताओं में उत्साह,जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने दी शुभकामनाएं

-संवाददाता-

सूरजपुर,16 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) छत्तीसगढ़ के प्रदेश नेतृत्व ने संगठन को और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से नई संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की है, इन नियुक्तियों के तहत शुभम जायसवाल को सरगुजा संभाग का संगठन प्रभारी तथा लोकेश साहू को संभाग का सहप्रभारी नियुक्त किया गया है, वहीं,कोमल पटेल को सूरजपुर जिले का संगठन प्रभारी एवं आनंद ताम्रकार को जिला सहप्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन नियुक्तियों के बाद सूरजपुर सहित पूरे सरगुजा संभाग के भाजयुमो कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के निर्णय का स्वागत करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं, भाजयुमो

सूरजपुर के जिलाध्यक्ष देव गुप्ता ने शुभम जायसवाल, लोकेश साहू, कोमल पटेल और आनंद ताम्रकार को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व और संगठनात्मक अनुभव से सरगुजा संभाग एवं सूरजपुर जिले में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी, उन्होंने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी युवाओं को संगठन से जोड़ने, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनके मार्गदर्शन में भाजयुमो सूरजपुर और अधिक सक्रियता के साथ कार्य करेगा तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए नए अभियान चलाए जाएंगे, प्रदेश नेतृत्व की इस घोषणा के बाद से ही भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच खुशी का माहौल है।

सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से कार्यकर्ता नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने भी विश्वास जताया है कि नई टीम आगामी संगठनात्मक गतिविधियों और अभियानों को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी।

CMYK

शहर पूछ रहा है-यदि कोई संबंध नहीं था तो शब्बीर आलम का नाम राजहंस से जुड़ा कैसे?

इरशाद अहमद की सफाई से नहीं थमे सवाल,शब्बीर आलम और राजहंस कनेक्शन पर जांच की निगाहें...

'साजिश' बताकर बचाव,लेकिन जवाब नहीं मिला...शब्बीर आलम प्रकरण में नए सवाल खड़े...

**राजहंस को बदनाम करने की साजिश या सच से बचने की कोशिश?
इरशाद अहमद के बयान पर उठा नया प्रश्न**

15 दिन बाद आई सफाई,लेकिन शहर पूछ रहा...आखिर शब्बीर आलम का नाम बार-बार क्यों जुड़ा?

इरशाद अहमद ने मीडिया पर उठाए सवाल,लेकिन शब्बीर आलम प्रकरण में खुद कई सवालों के जवाब अधूरे...

शब्बीर आलम से कोई रिश्ता नहीं...फिर वर्षों तक शहर में क्यों होती रही चर्चा?

राजहंस,बैतूल और शब्बीर आलम... सफाई आई,लेकिन संदेह अभी भी कायम

घटना हुई, एफआईआर हुई,आरोपी फरार हुए...फिर मीडिया ने आखिर क्या गलत लिखा?

सिर्फ सफाई नहीं,जवाब चाहिए...शब्बीर आलम प्रकरण में इरशाद अहमद के बयान से बढ़े सवाल

15 दिन बाद सामने आए इरशाद अहमद...बोले 'साजिश',लेकिन शब्बीर आलम,बैतूल और राजहंस कनेक्शन पर उठते सवालों का जवाब अब भी बाकी

-संवाददाता-
अंबिकापुर,16 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

झारखंड के धनबाद स्थित चर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त

फरार गैंगस्टर शब्बीर उर्फ साबिर आलम के अंबिकापुर में वर्षों तक कथित रूप से रहने और बाद में झारखंड पुलिस की कार्रवाई के दौरान फरार हो जाने के मामले ने पूरे सरगुजा संभाग की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं,इस मामले में राजहंस बस से जुड़े बैतूल खान के विरुद्ध अपराध दर्ज हो चुका है और वे भी फरार बताए जा रहे हैं,इसी बीच घटना के लगभग 15 दिन बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े संचालक इरशाद अहमद पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा।

इरशाद अहमद ने अपने बयान में राजहंस बस, बैतूल खान और अपनी कंपनी को निर्दोष बताते हुए पूरे घटनाक्रम को कुछ प्रतिस्पर्धी बस संचालकों की साजिश करार दिया, उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में शब्बीर आलम का एक रुपये का भी निवेश नहीं है और यदि ऐसा साबित हो जाए तो वे किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं,लेकिन उनके बयान के बाद जितने सवाल खत्म होने चाहिए थे, उससे कहीं अधिक नए सवाल खड़े हो गए हैं।

15 दिन तक चुप्पी क्यों, अब सफाई क्यों?- घटना 29 जून की है, झारखंड पुलिस अंबिकापुर पहुंची, गैंगस्टर को पकड़ने का प्रयास हुआ, विवाद हुआ, आरोपी फरार हुआ, बाद में एफआईआर दर्ज हुई, बैतूल खान फरार बताए गए और मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, इन सभी घटनाओं के बाद करीब 15 दिन तक कोई सार्वजनिक पक्ष सामने नहीं आया, अब जबकि पुलिस जांच आगे बढ़ रही है और पूरे मामले की चर्चा प्रदेशभर में हो रही है,तब इरशाद अहमद मीडिया के सामने आए, यही पहला प्रश्न लोगों के मन में है कि यदि शुरुआत से ही सारी बातें गलत थीं तो तत्काल सामने आकर उनका खंडन क्यों नहीं किया गया? आखिर 15 दिन बाद ही सफाई देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

राजहंस को बदनाम करने की साजिश या सवालों से बचने की कोशिश?- इरशाद अहमद ने अपने पूरे बयान में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि कुछ बस ऑपरेटर उनकी कंपनी को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं,उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय कुछ लोग मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब कर रहे हैं,लेकिन लोगों का कहना है कि यदि केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ही कारण है, तो फिर झारखंड पुलिस की कार्रवाई, एफआईआर और पूरे घटनाक्रम को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? सवाल यह भी है कि यदि सब कुछ केवल साजिश है, तो पुलिस ने अपराध दर्ज क्यों किया?

घटना हुई या नहीं हुई?

इरशाद अहमद ने मीडिया की खबरों को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मीडिया ने गलत लिखा,लेकिन यहां भी कई प्रश्न खड़े होते हैं,क्या झारखंड पुलिस वास्तव में अंबिकापुर नहीं आई थी? क्या शब्बीर आलम को पकड़ने की कार्रवाई नहीं हुई? क्या पुलिस के सामने विवाद नहीं हुआ? क्या आरोपी फरार नहीं हुआ? यदि यह सब हुआ,तो फिर मीडिया ने ऐसा क्या गलत लिखा जिसके कारण पूरे घटनाक्रम को गलत बताया जा रहा है?

यदि मीडिया गलत थी तो जानकारी आई कहां से....?

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों,प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी सामने आई, वही विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुई,बाद में पुलिस ने स्वयं भी अपराध दर्ज किया,ऐसे में यह प्रश्न भी उठता है कि यदि मीडिया पूरी तरह गलत थी,तो फिर मीडिया तक वही जानकारी कैसे पहुंची? क्या प्रत्यक्षदर्शियों ने झूठ बोला? क्या पूरे मोहल्ले ने गलत अफवाह फैलाई? क्या झारखंड पुलिस ने गलत जानकारी दी? या फिर वास्तविक घटनाक्रम वही था जिसकी चर्चा पूरे शहर में हुई?

सबसे बड़ा सवाल—शब्बीर आलम का नाम आखिर राजहंस से जुड़ा कैसे?- इस पूरे मामले का सबसे अहम प्रश्न आज भी यही बना हुआ है,यदि शब्बीर आलम का बैतूल खान,राजहंस बस या ट्रांसपोर्ट कंपनी से कोई संबंध नहीं था,तो वर्षों से शहर में उसका नाम राजहंस बस के साथ क्यों जोड़ा जाता रहा? बस स्टैंड पर,परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के बीच,स्थानीय मोहल्लों में और आम नागरिकों के बीच यह चर्चा क्यों होती रही कि शब्बीर आलम राजहंस बस के संचालन और देखरेख में सक्रिय रहता था? क्या यह केवल अफवाह थी? यदि हां, तो वर्षों तक इसका खंडन क्यों नहीं किया गया?

बैतूल घटना के समय छत्तीसगढ़ में नहीं थे—क्या जांच इसका जवाब देगी?- इरशाद अहमद ने दावा किया कि घटना के दिन बैतूल खान छत्तीसगढ़ में ही नहीं थे और मोबाइल लोकेशन इसकी पुष्टि कर देगी,उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी,लेकिन दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि पुलिस ने बैतूल खान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है और उसके बाद से वे फरार बताए जा रहे हैं,अब सवाल यह है कि यदि बैतूल घटना से पूरी तरह अनभिज्ञ थे तो फिर उनके विरुद्ध अपराध दर्ज क्यों हुआ?

सिर्फ निवेश का सवाल नहीं,संबंधों का भी है- इरशाद अहमद ने कहा कि यदि शब्बीर आलम का उनकी कंपनी में एक रुपये का भी निवेश साबित हो जाए तो वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं,लेकिन पूरे मामले में केवल निवेश ही मुद्दा नहीं है,लोग यह भी जानना चाहते हैं क्या व्यक्तिगत संबंध थे? क्या नियमित संपर्क था? क्या आने-जाने का सिलसिला था? क्या कोई व्यावसायिक या सामाजिक संबंध थे? इन सवालों पर इरशाद अहमद ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

कंपनी की छवि बचाने की कोशिश या सच्चाई रखने का प्रयास?- उनके पूरे बयान को सुनने वाले कई लोगों का मानना है कि उनका अधिकतर ध्यान राजहंस बस और कंपनी की प्रतिष्ठा बचाने पर था,उन्होंने बार-बार कहा कि कंपनी को बदनाम किया जा रहा है,लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यदि संबंध नहीं थे तो शहर में इतने वर्षों से यह चर्चा क्यों थी?

क्या केवल प्रतिस्पर्धी बस संचालक ही सवाल उठा रहे हैं?

इरशाद अहमद ने कहा कि कुछ बस संचालक उनकी सफलता से परेशान हैं,लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केवल वही लोग सवाल उठा रहे हैं? या फिर आम नागरिक,स्थानीय निवासी,मोहल्ले के लोग और पुलिस कार्रवाई देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं? यदि पूरा शहर एक जैसी चर्चा कर रहा है तो क्या उसे केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा कहकर खारिज किया जा सकता है?

अब जवाब केवल जांच दे सकती है...

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, झारखंड पुलिस और सरगुजा पुलिस दोनों अपने-अपने स्तर पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही हैं,बैतूल खान फरार बताए जा रहे हैं,शब्बीर आलम अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसके नेटवर्क की जांच चल रही है,ऐसी स्थिति में इरशाद अहमद का बयान जांच का स्थान नहीं ले सकता,ठीक वैसे ही मीडिया में प्रकाशित आरोप भी अंतिम सत्य नहीं माने जा सकते, अब यह देखना होगा कि पुलिस तकनीकी साक्ष्यों,मोबाइल लोकेशन, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान,दस्तावेजों और उपलब्ध अन्य प्रमाणों के आधार पर किन निष्कर्षों तक पहुंचती है,लेकिन इतना तय है कि यह मामला अब केवल एक फरार गैंगस्टर का नहीं रह गया है। यह अंबिकापुर की सुरक्षा व्यवस्था,पुलिस की कार्यप्रणाली, स्थानीय नेटवर्क,ट्रांसपोर्ट कारोबार और सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा मामला बन चुका है। जब तक इन सभी प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर जांच के माध्यम से सामने नहीं आते, तब तक यह पूरा प्रकरण चर्चा और विवाद के केंद्र में बना रहेगा।

धान रोपाई कर लौट रहीं महिला मजदूरों से भरी पिकअप पलटी,दो की मौत,दर्जनों घायल

-संवाददाता-
बलरामपुर,16 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो महिला मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य घायल हो गईं। हादसा जरगिमा-जुड़वानी गांव के पास उस समय हुआ,जब तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार,पिकअप में 20 से 25 महिला मजदूर सवार थीं। सभी महिलाएं परेवा गांव में धान रोपाई का काम पूरा कर अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान जरगिमा-जुड़वानी मार्ग पर वाहन का चालक नियंत्रण खो बैठा और पिकअप सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के

ग्रामीण तत्काल मदद के लिए पहुंच गए। दुर्घटना में दो महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई महिलाएं घायल हो गईं। घायलों में तीन महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अन्य घायलों का इलाज शंकरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही शंकरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

100 दिन जेल में रहा कर्मचारी...अब सवालों के घेरे में पूरी कार्रवाई

1.07 करोड़ गबन मामले में जांच रिपोर्ट ही नहीं मिली,पीएमओ और आईजी के दखल से खुलने लगीं परतें

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

पशुपालन विभाग के बहुचर्चित 1.07 करोड़ रुपए के कथित गबन मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। जिस विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक ग्रेड-दो प्रदीप कुमार अंबष्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, वही जांच रिपोर्ट पुलिस को कभी मिली ही नहीं। इतना ही नहीं, पुलिस ने न्यायालय में पेश चालान में स्पष्ट उल्लेख किया कि कथित गबन की विभागीय जांच होना ही नहीं पाई गई। इस खुलासे के बाद पूरे मामले में विभागीय कार्रवाई, पुलिस विवेचना और गिरफ्तारी की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। मामला 25 फरवरी 2026 का है, जब प्रभारी उप संचालक पशुपालन डॉ. आर.पी. शुक्ला ने कोतवाली थाने में आवेदन देकर पांच सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रदीप कुमार अंबष्ट पर 1.07 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने करीब 100 दिन बिताए। बाद में उन्हें जमानत मिली। लेकिन 29 मई को जब पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। चालान के साथ वह विभागीय जांच प्रतिवेदन संलग्न ही नहीं था,जिसके आधार पर अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपने चालान में यह भी उल्लेख किया कि कथित गबन की जांच किया जाना नहीं पाया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रभारी उप संचालक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 के तहत नोटिस

जारी कर जांच रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज मांगे,लेकिन विभाग की ओर से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। पुलिस ने जांच समिति के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए। सदस्यों ने बताया कि उन्हें आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे,इसलिए उन्होंने कोई जांच नहीं की। इस बीच यह भी सामने आया कि प्रदीप कुमार अंबष्ट ने एफआईआर दर्ज होने से करीब ढाई महीने पहले,15 दिसंबर 2025 को विभाग के सचिव,संचालक, संभागायुक्त,कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर उन्हें झूठे मामले में फंसाए जाने की आशंका जताई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि कार्यालयीन समय में सभी अभिलेख देखने के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन नियमों के तहत कैशबुक कार्यालय से बाहर नहीं ले जाई जा सकती। प्रकरण में एक और सवाल यह भी उठ रहा है कि प्रभारी उप संचालक ने 10 अक्टूबर 2025 को लेखा शाखा का प्रभार अपने पास ले लिया था। इसके बावजूद करीब चार महीने बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। इस अवधि में यदि गबन के आरोप सही थे तो विभागीय जांच पूरी कर आवश्यक दस्तावेज जुटाए जा सकते थे,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। प्रदीप कुमार के स्वजन ने पीएमओ में शिकायत कर पूरे प्रकरण को सुनियोजित साजिश बताया। शिकायत पर पीएमओ ने सरगुजा कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने भी पुलिस अधीक्षक से पूछा है कि बिना विभागीय जांच रिपोर्ट और ठोस दस्तावेजों के अपराध दर्ज कर शासकीय कर्मचारी की तत्काल गिरफ्तारी क्यों की गई। उन्होंने विवेचना अधिकारी की भूमिका की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अब पीएमओ और आईजी के हस्तक्षेप के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद बढ़ गई है। यह मामला केवल कथित गबन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिना पर्याप्त दस्तावेज और जांच के किसी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई किए जाने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

ब्लड प्रेशर की तीन गोलियां खानी पड़ती...परेश रावल ने इस वजह से छोड़ा था पॉलिटिक्स,12 साल बाद किया खुलासा

अभिनेता परेश रावल ने 2019 में राजनीति छोड़ने का कारण बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत अधिक समर्पण की आवश्यकता होती है।

क्या आप जानते हैं कि जाने माने अभिनेता परेश रावल एक समय राजनीति में बहुत सक्रिय थे। सिल्वर स्क्रीन पर लोगों को हंसाने वाले परेश 2014 से 2019 तक एक मुख्य पार्टी का हिस्सा रहे। एक्टर बीजेपी के टिकट पर गुजरात की अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से 2014 के आम चुनाव में जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि 2019 में एक्टर ने राजनीति छोड़ दी। इसका क्या कारण था और उन्हें क्यों ये फैसला लेना पड़ा इस पर परेश रावल ने बात की।

एक्टर ने क्यों छोड़ी राजनीति?

विक्की लालवानी के पॉडकास्ट पर बात करते हुए एक्टर ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है। उन्हें लगा कि एक्टिंग करियर जारी रखते हुए वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। परेश रावल ने अपने अनुभव के बारे में बात करते कहा कि इस काम की असलियत वैसी नहीं थी,जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने माना कि काम का बोझ, लगातार यात्रा और जिम्मेदारियों का उन पर बुरा असर पड़ा।

बहुत भगना पड़ता था : परेश

परेश ने कहा, मैं 2014 में जब गया पॉलिटिक्स में,उसके बाद मेरा शुरू हुआ। बीपी तो था पर तीन गोलियां लेना मेरा उसके बाद शुरू हुआ है क्योंकि आपको काम करना है। हम ऐसा मानते हैं कि पॉलिटिशियन फुल एसी करके बैठे रहते हैं, कोई पैर दबाता है,काजू-किश्मिश खाते हैं। वहां गए तो पता चला कितना काम कराते हैं। भगा भगा के थका देते हैं।परेश रावल ने बताया कि वो वहां सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए गए थे। एक्टर ने कहा-मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मेरा काम नहीं है। मैंने लिमिटेड टाइम के लिए ही गया था। मेरी समझ नहीं है। ये एक नोबेल काम है और इसके लिए पूरा अंदर रहना पड़ेगा। पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ही आप रह पाओगे। फिलहाल परेश रावल राजनीति छोड़ पूरे तरीके से बॉलीवुड को अपना समय दे रहे हैं।

जी वी प्रकाश की इम्मोर्टल की रिलीज़ 4 सितंबर तक के लिए टाल दी गई

डायरेक्टर मरियप्पन चिन्ना की हॉरर थ्रिलर इम्मोर्टल के मेकर्स ने अनाउंस किया कि उनकी फिल्म अब इस साल 4 सितंबर को दुनिया भर में स्क्रीन पर आएगी। जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि यह फिल्म पहले इस साल 23 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। डायरेक्टर एच विनोथ की लंबे समय से इंतज़ार की जा रही जन नायकन के मेकर्स, जिसमें एक्टर विजय लीड रोल में हैं,ने बुधवार को अनाउंस किया कि उनकी फिल्म 23 जुलाई को रिलीज़ होगी, इम्मोर्टल के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज़ को 4 सितंबर तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अपनी एक्स टाइमलाइन पर, जी वी प्रकाश ने लिखा, थलपति वंधा थल्ली पोयी धाने आगनुम। अधुवुम एक आखिरी बार. (जब थलपति आएगा, तो हमें रास्ता बनाना होगा। वह भी, एक आखिरी बार।) बेस्ट ऑफ़ लक टीम इमोर्टल आपके सपोर्ट और प्यार से 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज़ होगी जी वी प्रकाश ने इस साल मई में ही अनाउंस किया था कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है। सोर्स ने कहा था कि मेकर्स शुरू में फिल्म को इस साल मई में रिलीज़ करने का सोच रहे थे। हालांकि,फिर उन्होंने फिल्म की रिलीज़ डेट 23 जुलाई चुनी। अब, हालात ने मेकर्स को फिल्म की रिलीज़ 4 सितंबर तक आगे बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है।

पिछले साल जब से मेकर्स ने फिल्म का एक मज़ेदार और

एंटरटेनिंग टीज़र रिलीज़ किया है, तब से फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। अपनी एक्स टाइमलाइन पर टीज़र शेयर करते हुए, जी वी प्रकाश कुमार ने तब कहा था,आप सभी के लिए यह टीज़र है...मिस्ट्री वर्ल्ड अब सामने आ रहा है। टीज़र एक मज़ेदार रोमांटिक नोट पर शुरू होता है। इसमें जी वी प्रकाश,जो एक डाई हार्ड रोमांटिक हैं,एक दोस्त से बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, सोचो कैसा होगा अगर मेरे जैसा हैंडसम लड़का और एक बहुत खूबसूरत लड़की एक ही घर में रहें। दोस्त जवाब देता है,यह जलन पैदा करने वाला होगा।इस पर, जी वी प्रकाश खुशी से कहते हैं, ज़रूर होना चाहिए। फिर टीज़र में जी वी प्रकाश एक्ट्रेस कयादु लोहार के साथ एक फ्लैट में बात करते हुए दिखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जिसके बारे में वह कुछ समय पहले अपने दोस्त से बात करते हुए देखे गए थे। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं, तो क्या तुम मुझे गलत समझोगी,वह उससे पूछता है और वह जवाब देती है, तुम वैसे भी कुछ गलत ही पूछोगे। टीज़र से यह साफ़ है कि फ़िल्म में जी वी प्रकाश का किरदार कयादु लोहार के किरदार में रोमांटिक रूप से दिलचस्पी रखता है। वह उससे कहता है,मेरे कमरे में मच्छरों की बहुत समस्या है जिस पर वह जवाब देती है, मेरे कमरे में चमगादड़ों की वजह से समस्या है। क्या यह ठीक है? तभी हॉरर फ़ेज़ शुरू होता है। वह आधी रात को उठता है और कीहोल से देखता है, तो उसे चमगादड़ के चेहरे वाला एक जानवर मिलता है! फिल्म में जी वी प्रकाश कुमार और कयादु लोहार के अलावा, टीएम कार्तिक,कुमार नटराजन,लोल्लू सभा मारन,आदित्य कथिर, अर्शु महारजन,पेमा त्सामचो और सुनीता श्रेष्ठ जैसे कई एक्टर भी हैं। टेक्निकल तौर पर,इस फिल्म को अरुणकुमार धनसेकरन ने प्रोड्यूस किया है,इसकी सिनेमैटोग्राफी अरुण राधाकृष्णन ने की है और म्यूजिक सैम का है। फिल्म की एडिटिंग सैन लोकेश ने की है जबकि आर्ट डायरेक्शन शिवा शंकर ने किया है। फिल्म के स्टंट आर. शक्ति सरवनन ने कोरियोग्राफ किए हैं जबकि डांस सबरीश ने कोरियोग्राफ किए हैं।

बिजी लाइफस्टाइल और भरपूर एनर्जी:सोनाली बेंद्रे

एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने बताया है कि बिज़ी दिनों में उन्हें एनर्जेटिक रहने में क्या मदद करता है। इंस्टाग्राम पर,'सरफ़रोश' एक्ट्रेस ने अपने डेली रूटीन और मोटिवेशन के सोर्स के बारे में बताया जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। सोनाली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के ज़रिए अपने बिज़ी दिन की एक झलक शेयर की। क्लिप में, एक्ट्रेस अपने पैक्ड शेड्यूल को मैनेज करते हुए एनर्जेटिक रहने के लिए कॉफ़ी पर डिपेंडेंट दिखीं। उन्होंने अपने फ़ूड ब्रेक की भी एक झलक दिखाई, जिसमें वे कुछ घंटों के बाद खाना और एक और कप कॉफ़ी का मज़ा ले रही थीं। कैप्शन के लिए, उन्होंने बस लिखा कॉफ़ी से पावर्ड एक बिज़ी दिन। वीडियो में,सोनाली ने कहा,मुझे कॉफ़ी चाहिए,प्लीज़। इस बीच,वर्क फ्रंट पर,बेंद्रे हाल ही में वेब सीरीज़ 'राख' में नज़र आईं। शो के रिलीज़ के बाद बातचीत में,एक्ट्रेस ने बताया कि सेट पर आने से पहले ही उनका 50 प्रतिशत काम हो चुका था। मेरे पास काम करने के लिए बहुत बढ़िया मटीरियल था। तो,सच कहूँ तो,मेरा 50 प्रतिशत काम पहले ही हो चुका था। मैं कहूँगा कि 50 प्रतिशत से ज़्यादा काम पहले ही हो चुका था क्योंकि उन्होंने मुझे काम करने के लिए इतना बढ़िया मटीरियल दिया था। उसके बाद,मुझे बस उसमें कुछ चीज़ें जोड़नी थीं ताकि वह मेरा अपना बन जाए। तो,उनकी वजह से, यह एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैटर था जो मुझे दिया गया था। अभी के लिए,मैं कहूँगा कि मेरे लिए डायलॉग न होना आसान था क्योंकि पहले ज़िंदगी में,आप पूरा पेज पढ़कर याद रख सकते थे। लेकिन मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। इसलिए,यह बात कि मुझे डायलॉग याद नहीं रखने पड़ते,असल में मेरे लिए मज़ेदार थी।

सोहेल खान का खुलासा,बोले... मुझे सेक्सुअली हैरेस किया गया

बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान ने हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़े एक बेहद निजी और भावुक अनुभव को साझा किया है। प्राइम वीडियो के रियलिटी शो अलायंस में सोहेल खान ने अपने बचपन के एक दर्दनाक ट्रॉमा के बारे में खुलासा किया।

उन्होंने बताया कि कम उम्र में उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था और शर्म व डर के कारण उन्होंने इस बात को कई सालों तक अपने परिवार से छिपाकर रखा। शो के दौरान सोहेल खान ने बचपन में हुई बुलिंग और उससे जुड़े अनुभवों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि बचपन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरना उनके लिए काफी मुश्किल था। उस समय वह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ जो हुआ, उसके बारे में किससे बात करें और कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करें।

सोहेल ने बताया कि शर्म और डर की वजह से उन्होंने यह बात लंबे समय तक अपने पिता को भी नहीं बताई। हालांकि, बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने पिता के साथ इस अनुभव को साझा किया। अभिनेता ने कहा कि बचपन में होने वाली ऐसी घटनाएं किसी भी व्यक्ति के मन पर गहरा असर छोड़ सकती हैं और कई बार बच्चे डर या झिझक के कारण अपने साथ हुई बातों को किसी से नहीं कह पाते। शो में बातचीत के दौरान सोहेल खान ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि वह अपने बेटों से अक्सर बात करते रहते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं वे भी किसी तरह की परेशानी, दबाव या गलत अनुभव से तो नहीं गुजर रहे हैं। उनका मानना है कि माता-पिता को बच्चों के साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी परेशानियां खुलकर बता सकें। सोहेल खान का यह खुलासा सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों और शो के दर्शकों ने उनकी हिम्मत की सराहना की है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर बात करना जरूरी है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी अपनी परेशानियों को साझा करने और मदद लेने की प्रेरणा मिल सकती है। अभिनेता ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि बचपन में होने वाले मानसिक दबाव और बुलिंग का असर लंबे समय तक रह सकता है। कई बच्चे ऐसी घटनाओं को अपने अंदर दबाकर रखते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।

90 दशक के तड़के के साथ लौटे अक्षय और सैफ हैवान का पहला लुक वायरल

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म 'हैवान' का फर्स्ट लुक बुधवार को सामने आया। यह दर्शकों को फिल्ममेकर प्रियदर्शन की बनाई फिल्म की गहरी और रहस्यमयी दुनिया से मिलवाता है। फर्स्ट लुक मिस्ट्री, खतरे और कभी न खत्म होने वाले टेंशन से भरा है, और 2026 की सबसे बेसब्री से इंतज़ार की जाने वाली थ्रिलर में से एक के लिए माहौल बनाता है। फिल्म में श्रेया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम रोल में हैं।

यह फिल्म अक्षय कुमार और सैफ अली खान की रीयूनियन है। सैफ और अक्षय ने पिछली बार 'टशन' में साथ काम किया था, जो कमर्शियल और क्रिटिकल तौर पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी। फिल्म में बोमन ईरानी, सैयामी खेर और श्रेया पिलगांवकर जैसे शानदार कलाकार भी अहम रोल में हैं। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में और अक्षय कुमार और सैफ अली खान के बड़े पर्दे पर एक साथ आने के साथ,हैवान 2026 के सबसे बड़े थिएटर इवेंट्स में से एक बनने के लिए तैयार है। हैवान को केव्हीएन प्रोडक्शंस ने थेस्पियन फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, और वेंकट के नारायण और शैलजा देसाई फेन ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म पिछले साल फ्लोर पर आई थी। उस समय, अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बीएसबी वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह और सैफ डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ आराम से बात करते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, हम सब ही हैं थोड़े से शैतान कोई ऊपर से संत,कोई अंदर से हैवान... आज अपने सबसे पसंदीदा कैप्टन प्रियदर्शन सर के साथ हैवान की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। लगभग 17 साल बाद सैफ के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। चलो हैवानियत शुरू करते हैं! हैवान को केव्हीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के तहत वेंकट के नारायण और शैलजा देसाई फेन ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

खेल समाचार

इंग्लैंड की धरती पर विराट कोहली ने रचा इतिहास

कार्डिफ,16 जुलाई 2026। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वनडे प्रारूप के बेताज बादशाह ने अबकि बार राहुल द्रविड़ के एक अनोखे रिकॉर्ड को तोड़ा है। विराट अब भारत की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ उनकी ही धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में किंग कोहली ने ये कारनामा किया।

विराट कोहली ने रचा इतिहास

विराट कोहली ने इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले राहुल द्रविड़ इस मामले में सबसे आगे थे। उन्होंने 2645 रन बनाए थे।

जबकि कोहली दूसरे वनडे में 2646 रन बनाकर उनसे आगे निकल गए। इस लिस्ट में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 2626 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। टॉप-5 में रोहित शर्मा और सौरव गांगुली भी शामि हैं। दोनों पूर्व कप्तानों ने इंग्लिश सरजमीं पर क्रमशः 2,308 और 1,949 रन बनाए।

इंग्लैंड में विराट कोहली का शानदार रिकॉर्ड

इंग्लैंड में विराट कोहली के आंकड़े बेहद शानदार हैं। 34 वनडे इंटरनेशनल की इतनी ही पारियों में उन्होंने 50 की औसत से 1354 रन बनाए हैं। जिसमें 1 शतक और 12 फिफ्टी शामिल हैं। इसके अलावा टेस्ट फॉर्मेट में 17 मुकाबलों की 33 पारियों में 2 सेंचुरी और 5 फिफ्टी समेत 33 की औसत से 1096 रन अपने खाते में जोड़े। टी20 इंटरनेशनल की 7 पारियों में 192 रन जड़े।

जड़ी 132वीं वनडे फिफ्टी

विराट कोहली ने इंजरी के बाद दमदार वापसी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में फिफ्टी जड़ी। खबर लिखने तक उन्होंने 51 गेंदों में 53 रन बना दिए हैं। वह एकदिवसीय क्रिकेट में 132वीं बार अर्धशतक का आंकड़ा पार कर चुके हैं। उनकी इस पारी में अबतक 7 चौके देखने को मिले हैं। इसके साथ ही विराट ने बतौर भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की धरती पर सबसे ज्यादा 33 फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले सचिन तेंदुलकर 32 अर्धशतक के साथ सबसे ऊपर थे।

पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में : जापान ओपन में चीनी खिलाड़ी हान यू को चटाई धूल

टोक्यो ,16 जुलाई 2026। पीवी सिंधु ने गुरुवार को जापान ओपन सुपर 750 में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने चीन की दुनिया की नंबर 5 खिलाड़ी हान यू को सीधे गेम में हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट ने शांत और अटैकिंग खेल दिखाते हुए सिर्फ़ 35 मिनट में 21-16, 21-14 से जीत हासिल की, जिससे चीनी शटलर के खिलाफ उनका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 8-1 हो गया। यह नतीजा सिंधु के इस सीज़न के सबसे ज़बरदस्त प्रदर्शनों में से एक था, जिसमें पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने शुरुआती चुनौती को पार करते हुए पांचवीं सीड के खिलाफ मैच पर पूरा कंट्रोल कर लिया। शुरुआती मुकाबले काफी करीबी रहे क्योंकि हान यू ने रफ़्तार बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सिंधु धीरे-धीरे मैच में जम गईं। एक बार जब उन्हें अपनी रेंज मिल गई, तो भारतीय खिलाड़ी ने सटीक शॉट प्लेसमेंट और बेसलाइन से ज़्यादा अग्रेसन के साथ रैलियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उनकी बेहतर कंसिस्टेंसी ने उन्हें पहले गेम के आखिरी स्टेज में आगे निकलने में मदद की, जिसे उन्होंने 21-16 से जीत लिया।

सूचना/ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं टेकनाथ राम/Teknath Ram पिता का नाम स्व. बुन्दवा राम, ग्राम सिंधमा थाना व तहसील राजपुर जिला बलरामपुर छ0ग0 का स्थायी निवासी हूँ। मेरे आधार संख्या 7946 7856 0752 में मेरा नाम टेकनाथ पैंकरा / Teknath Paikara अंकित हो गया है तथा मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम टेकनाथ राम / Teknath Ram अंकित है। मैं शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर सेवारत हूँ। मेरे सेवा पुस्तिका मे मेरा नाम टेकनाथ राम पैंकरा अंकित है। वर्तमान समय में उपरोक्त सभी नामों का एक मात्र व्यक्ति मैं ही हूँ। मैं अपने आधार कार्ड संख्या 7946 78560752 में नाम शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार अंकित करवाना चाहता हूँ जिस संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हूँ। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में अंकित नाम पर अपना नाम टैकनाथ पैंकरा/Teknath Paikara के स्थान पर अपना नाम टेकनाथ राम/Teknath Ram दर्ज करवाना चाहता हूँ, अगर किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करावे ।

स्थान- अम्बिकापुर
दिनांक-17/07/2026

भवदीय
टेकनाथ राम
मो0 नं0- 9926157893

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,तहसील भटगांव

रा.प्र.क्र.272,ब-121/2025-26

ईश्तहार

आम जनता ग्राम खोपा को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रीना आ0 स्व0 मनोहर जाति रजवार निवासी ग्राम सलका तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर द्वारा अपने पिता स्व0 मनोहर का ग्राम खोपा में मृत्यु दिनांक 15/02/2002 मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत् शुल्क अदा कर चालान की प्रति, शमथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक 21/07/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 09/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
जिला-सूरजपुर,छ0ग0

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर (छत्तीसगढ़)

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि बलरामपुर वनमण्डल के अंतर्गत काष्ठागार वाड्रफनगर में रखी इमारती लकड़ी / जलाऊ काष्ठ को निम्नलिखित तिथि व समय में ई-ऑक्शन द्वारा निवर्तन किया जाना है। इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्शन में अवश्य भाग लेवें। ई-ऑक्शन की शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार वाड्रफनगर से प्राप्त कर सकते हैं।

डिपो का नाम
काष्ठागार वाड्रफनगर
ई-नीलाम दिनांक 24.07.2026
समय -प्रातः 09 : 00 बजे से

क्र0	वनोपज का विवरण	नया काष्ठ		पुराना काष्ठ	
		लट्ठा	बल्ली /डेंगरी	लट्ठा (घ.मी.)	बल्ली /डेंगरी
		घ.मी.	नग	नग	
1	2	3	4	5	
A	इमारती काष्ठ				
1	सागौन	21.586	60	73.922	190
2	साल	1235.251	25	2787.132	937
3	साजा	25.289	-	252.630	132
4	तिन्सा	-	-	-	-
5	बीजा, शीशम, खम्हार	3.107	2	19.897	9
6	हल्दु, गुंडी, बांस	1.009	-	63.114	4
7	धावड़ा	8.673	-	10.250	81
8	अन्य मिश्रित (सेमल)	35.145	-	72.231	109
9	नीलगिरी	2.983	9	-	-
10	सलया	-	-	-	-
11	खैर काष्ठ	2.939	-	-	-
	योग :–	1335.982	96	3279.176	1462
क्र	प्रजाति विवरण				
1	जलाऊ चट्टा मिश्रित प्रजाति सा. 2.00 मी0 X 1.25 X 0.80 मी0	231 चट्टा		429 चट्टा	

टीप : 1 क्रेता को ई-ऑक्सन के पूर्व एम.एस.टी.सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2 क्रेताओं को ई-ऑक्सन के पूर्व क्रय लाटों के अपसेट प्राइज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत ई.एम.डी.की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थप्पी एवं फोटो एम. एस. टी. सी. ई-कॉमर्स पोर्टल में अपने आई.डी. से लॉगईन करके देख सकते हैं।

जी नंबर-262702133/3

वनमण्डलाधिकारी
बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

नाम परिवर्तन सूचना

मै हीरामनी उर्फ बदोलहीन पति श्री परमेश्वर जाति गोड़ निवासी नावापारा पडौली तहसील लुन्ड्रा जिला सरगुजा छ0ग0 की निवासी हूं । यह कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने नाम पर एक बीमा जिसकी पालिसी क्रमांक 207029405 कराई थी जिसमें मेरा नाम त्रृटीवश घर की पुकारु नाम बदोलहीन दर्ज हो गई हैं। जो कि वर्तमान में मेरे पास बोटर आईडी कार्ड बदोलहीन नाम से दर्ज है।
मेरी वोटर कार्ड द्वारा मै अपना नाम हीरामनी करा चुकी हूं जिसमे पासबुक एवं आधार में हीरामनी दर्ज है तथा अब मै अपना पालिसी क 207029405 को हीरामनी कराना चाहती हूं।

शपथग्रहिता
हीरामनी उर्फ बदोलहीन

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मैं शबनम बानो पति इमाम खान उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत सलका, तहसील- उदयपुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड क्रमांक 9632 6008 4122 में मेरे पुत्री का नाम जयमा परवीन (JAYMA PARVIN) दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पुत्री का सही व वास्तविक नाम ज़ैनब खान (ZAINAB KHAN) है।

अतः मेरी पुत्री के आधार कार्ड में सुधार कर उसके सही व वास्तविक नाम ज़ैनब खान (ZAINAB KHAN) दर्ज किया जाये। इस हेतु मेरे द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

शपथग्रहिता
शबनम बानो

सेवाग्राम पर विधानसभा में गरमाई सियासत....अजय चंद्राकर की टिप्पणी पर भूपेश बघेल ने जताई कड़ी आपत्ति

200 करोड़ रुपये के खर्च को लेकर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने सदन में तीखी बहस के बाद अजय चंद्राकर ने जताया खेद

रायपुर,16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को नवा रायपुर स्थित सेवाग्राम परियोजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने परियोजना पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाते हुए इसे एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता का परिणाम बताया। इस टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई,जिसके बाद सदन में कुछ देर तक जोरदार बहस का माहौल बना रहा। विधानसभा में सेवाग्राम की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति से जुड़े प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सेवाग्राम परियोजना को 10 मार्च 2022 को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर ग्राम के विचार को मूर्त रूप देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना तथा कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। मंत्री ने सदन को बताया कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक परियोजना के लिए कुल 129 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। इसमें मल्टीपरपज डाइनिंग हॉल,सामुदायिक किचन और प्रसाधन कक्ष के निर्माण पर 3.72 करोड़ रुपये तथा अन्य निर्माण कार्यों पर 104.05 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेवाग्राम के सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं,हालांकि इसके संचालन के लिए अभी तक अलग से कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्वीकृत नहीं की गई है। मंत्री के जवाब के बाद भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता की वजह से करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल खड़े हुए और कड़ा विरोध जताते हुए टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बढ़ते विवाद के बीच अजय चंद्राकर ने सदन में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि उनकी टिप्पणी से भूपेश बघेल की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। इसके बाद सदन की कार्यवाही सामान्य हो सकी।

आदिवासी क्षेत्रों में अधिक मैदानी क्षेत्रों में कम खाद देने का आरोप : कृषिमंत्री रामविचार नेताम ने कहा...भारत सरकार प्लान के तहत आवंटन करती है। हम किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराते हैं। लक्ष्य से कई गुणा अधिक खाद देने की दलेश्वर ने की जांच की मांग की।

महुआ नीति की गड़बड़ी पर उठाए सवाल...

नेता प्रतिपक्ष ने कहा- वन क्षेत्र के तालाब पर आदिवासी से टैक्स नहीं ले सकते,लेकिन मौजूदा नीति में टैक्स का प्रावधान है। मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में घोषणा करते हुए कहा...नई नीति पर काम जारी, सारी विसंगतियों को दूर करेंगे। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा...मौजूदा नीति 2022 में भूपेश सरकार ने बनाई थी। 10 हजार हेक्टेयर का ठेका पंजीकृत व्यक्ति या संस्था को देने का प्रावधान किया गया। इससे स्थानीय लोग, समुदाय का हक मारा गया। नई नीति में इन सब विसंगतियों को दूर किया जाए। मंत्री राम विचार नेताम ने कहा- निश्चित रूप से पॉलिसी में बदलाव करेंगे।

उर्वरक आवंटन का मुद्दा उठा

कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने कुछ स्थानों में लक्ष्य के विरुद्ध ज्यादा खाद देने का आरोप लगाया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दी जानकारी- 14 लाख 6 हजार 555 मीट्रिक टन खाद आवंटन हुआ। सहकारिता क्षेत्र में 64% और निजी क्षेत्र में 36% खाद दिया गया। विधायक दलेश्वर साहू ने ज्यादा खाद देने की जांच कराने की मांग की।

बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाओं को लेकर सवाल

कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने मल्हार से प्राप्त ऐतिहासिक बालार्जुन की ताम्रपट्टिकाओं को लेकर सवाल उठाया। विधायक राघवेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में देश को यह बताया था कि यह ऐतिहासिक ताम्रपत्र ब्राह्मी और पाली भाषा में लिखा गया है। जबकि आज सदन में विभागीय मंत्री कह रहे हैं कि यह ब्राह्मी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रधानमंत्री जब देश के सामने कुछ कहते हैं, तो पूरा देश उसे सही मानकर उस पर अटूट भरोसा करता है। लेकिन मंत्री का यह जवाब देश और सदन को पूरी तरह गुमराह करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी गलत तथ्य पेश कर मंत्री से गलत जवाब दिलवा रहे हैं। राघवेंद्र सिंह ने मांग की कि सदन को गुमराह करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या तत्काल कार्रवाई की जाएगी?

मंत्री बोले-दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह के सवाल पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने विपक्ष के आरोप की गंभीरता को देखते हुए सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं,जिन्होंने यह विसंगतिपूर्ण जानकारी तैयार की है, हम उनके खिलाफ निश्चित रूप से जांच कर कड़ी कार्रवाई करेंगे।

छत्तीसगढ़ में लागू हुआ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026,अधिसूचना जारी...

रायपुर,16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सरकार ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। राज्य शासन ने पूरे प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 को पूरी तरह से प्रभावी कर दिया है। इस कानून के लागू होते ही अब धोखे से धर्म बदलने वालों की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। राजपत्र में इस कानून का प्रकाशन होने के बाद से पुलिस और प्रशासन को विशेष शक्तियां मिल गई हैं। यही वजह है कि अब प्रदेश में किसी भी नागरिक को डराकर या लालच देकर धर्म बदलने पर सीधे जेल जाना होगा। नए नियमों के तहत सजा की अवधि को पहले के मुकाबले काफी कड़ा कर दिया गया है।

सामूहिक धर्मांतरण पर अब सीधे आजीवन कारावास : इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक या धोखाधड़ी से सामूहिक धर्मांतरण कराता है,तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। अदालत ऐसे दोषियों को अब सीधे आजीवन कारावास तक की सजा सुना सकती है। इसके साथ ही दोषियों पर 25 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पीड़ित के आधार पर तय होगी सजा की अवधि : अगर धर्म परिवर्तन की शिकार कोई महिला,नाबालिग या अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग का व्यक्ति होता है,तो कानून और अधिक सख्त हो जाएगा। इस स्थिति में दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम 20 साल तक की जेल हो सकती है। सामान्य मामलों में भी अब 7 से 10 साल की सजा के साथ कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है। अक्सर देखा गया है कि सिर्फ शादी करने के उद्देश्य से लोग अपना मूल धर्म बदल लेते हैं। नए अधिनियम में इस पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब केवल विवाह के उद्देश्य से किया गया धर्म परिवर्तन पूरी तरह अमान्य होगा और उस शादी को शून्य घोषित कर दिया जाएगा।

राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथयात्रा में हुए शामिल

रथयात्रा हमारी आस्था,लोकसंस्कृति,सामाजिक समरसता और जनभागीदारी का जीवंत महापर्व : सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर,16 जुलाई 2026। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में आयोजित भव्य रथयात्रा महोत्सव में शामिल हुए। दोनों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान जगन्नाथ,भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पारंपरिक श्छेरा-पहराश् की रस्म निभाते हुए प्रदेश वासियों की सुख-समृद्धि,शांति,उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं की आस्था,भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा। वैदिक मंत्रोच्चार,भजन-कीर्तन और जयघोष के बीच भगवान जगन्नाथ,भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशेष विधि-विधान के साथ मंदिर से रथ तक लाया गया। इसके पूर्व राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पारंपरिक रीति से सोने की झाड़ू द्वारा छेरा-पहरा की रस्म निभाकर रथमार्ग का प्रतीकात्मक शुद्धिकरण किया। इसके पश्चात महाप्रभु की प्रतिमाओं को श्रद्धापूर्वक रथ पर विराजित किया गया और रथयात्रा का शुभारंभ हुआ।

इस अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को रथयात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता, लोकपरंपरा और जन-जन की आस्था का महापर्व है। यह उत्सव समाज को सेवा, समर्पण, समानता और लोककल्याण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भगवान जगन्नाथ किसानों के आराध्य और अन्नदाता के रक्षक माने जाते हैं। उनकी कृपा से समय पर वर्षा होती है, खेतों में हरियाली आती है, धान की बालियों में दूध भरता है और किसानों के घरों में समृद्धि का आगमन होता है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि इस वर्ष प्रदेश में भरपूर वर्षा हो, कृषि समृद्ध हो,किसानों की मेहनत सफल हो और छत्तीसगढ़ निरंतर विकास एवं खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ता रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का दिव्य आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर बना रहे।

विधानसभा से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026 पारित

छत्तीसगढ़ में कारोबार करना होगा आसान,देश का पहला ट्रस्ट बेस्ड और रिस्क बेस्ड बिजनेस परमिशन सिस्टम

रायपुर,16 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा ने 'छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026' पारित कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए रिस्क बेस्ड और ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा। अधिनियम का उद्देश्य उद्योगों और कारोबार की स्थापना व संचालन की प्रक्रिया को आसान बनाना, अनावश्यक नियमों को कम करना, खासकर एमएसएमई के लिए पारदर्शी, तेज और उद्यम-अनुकूल माहौल तैयार करना है।

जोखिम के आधार पर मिलेगी मंजूरी

नई व्यवस्था में उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण उनके आकार और गतिविधियों के आधार पर होगा। कम जोखिम वाले छोटे कारोबारों को आसान और त्वरित मंजूरी मिलेगी। अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी जांच और तय समय में स्वीकृति की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इससे छोटे कारोबारियों को बड़ी परियोजनाओं जैसी जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

सेल्फ सर्टिफिकेशन से बढ़ेगी सुविधा

कम जोखिम वाले उद्यमों में बार-बार विभागीय निरीक्षण की जगह सेल्फ सर्टिफिकेशन या लाइसेंसधारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट अथवा अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाणन की सुविधा मिलेगी। इससे अनुमति प्रक्रिया तेज, आसान और जवाबदेह बनेगी।

हर साल लाइसेंस नवीनीकरण से मिलेगी राहत

अधिनियम के तहत हर वर्ष लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता खत्म होगी। जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू होने से उद्यमियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। इससे कारोबार के विस्तार पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा।

एमएसएमई को मिलेंगी कई बड़ी सुविधाएं : एमएसएमई इकाइयों को जल प्रदाय की अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर मिलेगी। सोसायटी या फर्म का पंजीयन तय समय में होगा। भवन अनुज्ञा सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी की जा सकेगी। तय समय में विभाग फैसला नहीं लेता है तो पात्र मामलों में अनुमति स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं में तकनीकी जांच और भौतिक निरीक्षण पहले की तरह जारी रहेगा। अधिनियम के तहत राज्य के 8 विभागों की 43 सेवाओं को जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली में शामिल किया गया है। जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका परिषद की मंजूरी के बाद नई सेवाएं भी जोड़ी जा सकेंगी।

तीन स्तर पर होगी निगरानी

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनेगी। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति जिम्मेदारी निभाएगी। दोनों समितियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में काम करेंगी। सरकार का अनुमान है कि इस सुधार से राज्य के 15 लाख से अधिक सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों को सीधा लाभ मिलेगा। भरोसे, स्व-घोषणा और समयबद्ध सेवाओं पर आधारित व्यवस्था से कारोबार शुरू करने में लगने वाला समय और लागत कम होगी। अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी और परीक्षण पहले की तरह जारी रहेगा।

पुराने फैसले का हवाला देकर नहीं मिल सकता,समान लाभ,हाईकोर्ट ने शिक्षकों की अपील खारिज

बिलासपुर,16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एलबी संवर्ग के शिक्षकों को समान लाभ देने की मांग वाली अपील खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि केवल किसी पुराने न्यायिक फैसले या विभागीय परिपत्र का हवाला देने भर से समान लाभ का अधिकार नहीं बनता। संबंधित कर्मचारी को यह भी साबित करना होगा कि उसके सेवा संबंधी तथ्य और परिस्थितियां उस पुराने मामले से पूरी तरह मेल खाती हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रकरण की सुनवाई की। मामला रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड में पदस्थ प्रधान पाठिका हेमलता बघेल तथा शिक्षिकाओं गीता साहू, मीरा साहू और मंजूषा जायसवाल का है। इनकी याचिका पहले एकलपीठ ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने 109 दिन की देरी से उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की। खंडपीठ ने देरी को माफ करते हुए अपील पर सुनवाई तो की, लेकिन मामले के गुण-दोष के आधार पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं ने 10 मार्च 2017 के विभागीय परिपत्र और सोना साहू प्रकरण का हवाला देते हुए समान लाभ दिए जाने की मांग की। वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस विवाद का निपटारा पहले ही पुष्पलता माणिकपुरी मामले में हो चुका है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि उनकी सेवा शर्तें और परिस्थितियां सोना साहू मामले के समान हैं। ऐसी स्थिति में केवल पुराने फैसले या विभागीय आदेश का उल्लेख कर समान लाभ नहीं दिया जा सकता।

जयंत वैष्णव बने मुख्यमंत्री सुरक्षा के नए एसपी, डीजीपी ने जारी किया आदेश हरीश राठौर के कोरिया एसपी बनने के बाद मिली नई जिम्मेदारी

रायपुर,16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक अहम प्रशासनिक नियुक्ति की गई है। जयंत वैष्णव को मुख्यमंत्री सुरक्षा का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में डीजीपी अरुण देव गौतम ने आदेश जारी कर दिया है। यह नियुक्ति हरीश राठौर के कोरिया जिले का पुलिस अधीक्षक बनाए जाने के बाद की गई है। उनके स्थान पर अब मुख्यमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी जयंत वैष्णव संभालेंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जयंत वैष्णव तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री सुरक्षा के एसपी का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

ई-20 पेट्रोल मामले में वाहन मालिक को बड़ी राहत उपभोक्ता आयोग ने नई कार देने का दिया आदेश

रायपुर,16 जुलाई 2026। इथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल को लेकर देशभर में चल रही बहस के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से वाहन उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक वाहन मालिक के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को शिकायतकर्ता की खराब कार वापस लेकर उसके स्थान पर उसी मॉडल की नई ई-20 अनुकूल कार उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार,रायपुर के सड्डू निवासी डॉ. प्रेमराज देवता ने जून 2024 में मारुति सुजुकी की जनवरी 2023 मॉडल की ग्रैंड विटारा स्ट्रांग हाइब्रिड जेटा प्लस कार खरीदी थी। वाहन खरीदने के कुछ समय बाद ही कार अचानक बंद होने लगी। कई बार अधिकृत सेवा केंद्र में जांच कराने पर उन्हें बताया गया कि पेट्रोल में मिलावट के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। इसके बावजूद ईंधन बदलने और आवश्यक मरम्मत कराने के बाद भी वाहन में बार-बार वही खराबी आती रही। इसके बाद डॉ. देवता ने सरकारी प्रयोगशाला में पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि ईंधन इंजन के अनुरूप नहीं था। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने वाहन विक्रेता और निर्माता कंपनी से संपर्क किया, लेकिन उन्हें यह कहकर कोई राहत नहीं दी गई कि समस्या ई-20 पेट्रोल के कारण उत्पन्न हुई है। इसके बाद डॉ. देवता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर किया। उन्होंने कहा कि यदि वाहन ई-20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं था,तो बिक्री के समय इसकी स्पष्ट जानकारी और आवश्यक सावधानियों से उन्हें अवगत कराया जाना चाहिए था। उन्होंने इस मामले में वाहन विक्रेता नेक्सा मैग्नेटो स्काई ऑटोमोबाइल्स तथा निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को पक्षकार बनाया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने माना कि संबंधित वाहन का इंजन ई-20 पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं था। आयोग ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने कई बार ईंधन बदला, पेट्रोल टैंक की सफाई कराई और नया पेट्रोल भरवाया, फिर भी वाहन बार-बार बंद होता रहा। इससे स्पष्ट है कि समस्या केवल ईंधन बदलने से दूर नहीं हुई। अपने निर्णय में आयोग ने कहा कि आधुनिक वाहनों में ईंधन की गुणवत्ता और वाहन की अनुकूलता के संबंध में उपभोक्ता को पूरी जानकारी देना निर्माता और विक्रेता की जिम्मेदारी है। यदि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उपभोक्ता को नहीं दी जाती है, तो यह सेवा में कमी मानी जाएगी।आयोग ने मारुति सुजुकी को आदेश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की खराब कार वापस लेकर उसके स्थान पर उसी मॉडल की नई, ई-20 ईंधन के अनुरूप कार उपलब्ध कराए। यदि कंपनी ऐसा करने में असफल रहती है, तो उसे वाहन की कीमत 18.29 लाख रुपये, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शुल्क 1.86 लाख रुपये तथा बीमा राशि 34,644 रुपये सहित कुल 20.50 लाख रुपये शिकायतकर्ता को लौटाने होंगे।

छत्तीसगढ़ में वर्षों से जमे संलग्न शिक्षकों पर सख्ती...आदेश नहीं मानने पर होगी 'ब्रेक इन सर्विस' की कार्रवाई

रायपुर,16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में वर्षों से विभिन्न शासकीय कार्यालयों में संलग्न होकर गैर-शैक्षणिक कार्य कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ अब शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें मूल संस्था में लौटने का आदेश दिया गया है, यदि वे निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ 'ब्रेक इन सर्विस' (सेवा हरण) की कार्रवाई का प्रस्ताव संचालनालय को भेजा जाएगा। इस आदेश के बाद लंबे समय से मंत्रालय,कलेक्टोरेट, राजस्व विभाग सहित विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत संलग्न कर्मचारियों में हलचल मच गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी पत्र में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 14 जुलाई 2026 को जारी संलग्नीकरण समाप्त करने संबंधी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। आदेश के अनुसार शासकीय कार्यालयों में कार्यरत सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपनी मूल पदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण करना होगा तथा ऑनलाइन एप के माध्यम से अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी होगी। संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के बाद अपनी मूल संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगे, उनकी समय-सीमा समाप्त होने से लेकर कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि को 'ब्रेक इन सर्विस' माना जाएगा। ऐसे सभी मामलों का प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को संचालनालय भेजना अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में वर्षों से बड़ी संख्या में शिक्षक और अन्य शिक्षा विभाग के कर्मचारी शिक्षण कार्य छोड़कर मंत्रियों के कार्यालय,कलेक्टोरेट,राजस्व विभाग तथा अन्य शासकीय कार्यालयों में संलग्न होकर काम कर रहे हैं।

आरआरबी परीक्षा में हाईटेक नकल का खुलासा...अंडरगारमेंट में मोबाइल छिपाकर पहुंचा अभ्यर्थी गिरफ्तार

रायपुर,16 जुलाई 2026। रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करने का मामला सामने आया है। रायपुर के सरोना स्थित परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन से प्रश्नों की फोटो खींचते हुए पकड़ा गया। डी.डी. नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को आईडीजेड सरोना स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की दूसरी पाली के दौरान कक्ष निरीक्षक को एक अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। निगरानी बढ़ाने पर सीसीटीवी फुटेज और जांच में पता चला कि वह परीक्षा कक्ष में छिपाकर लाए गए मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा था और कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे प्रश्नों की फोटो खींच रहा था। सुरक्षा बलों ने नाकाम की साजिश पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने डबल अंडरगारमेंट पहनकर उसके भीतर मोबाइल फोन छिपाया था, ताकि सुरक्षा जांच से बचकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सके। बरामद मोबाइल की जांच में परीक्षा के दौरान पूछे गए प्रश्नों की तस्वीरें भी मिलीं,जो स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रश्नों से मेल खाती थीं। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई,जिसके बाद डी.डी. नगर थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) तथा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा 10(1) के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)